सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

" मैं ईश्वर के हर निर्णय पर प्रसन्न हूं,
क्योंकि उसने मुझे पीड़ा सहने वालों की श्रेणी में रखा है,
न कि पीड़ा देने वालों में ...!! "

अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–154 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, बुधवार 24 जून 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

खास–खबर

जहां कभी आतंक और भय का माहौल था, वहां आज विकास, विश्वास और अवसरों का नया दौर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री के नेशन फर्स्ट संकल्प और सुरक्षा बलों के शौर्य से बस्तर में लौटी शांति और विकास की नई रोशनी– मुख्यमंत्री साय

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को विकास और जनविश्वास की विजय बताते हुए कहा है कि सरकार ने नक्सलवाद और माओवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया था और आज उसके सकारात्मक परिणाम पूरे देश के सामने हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी भय, हिंसा और अविश्वास का वातावरण था, वहां आज विकास, सुशासन और नई संभावनाओं का युग प्रारंभ हो चुका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य नागरिक निरंतर भय के साये में जीवन जीने को मजबूर थे। लोगों को अपनी सुरक्षा, आजीविका और सम्मान की चिंता रहती थी। विकास कार्यों को आगे बढ़ाना अत्यंत कठिन था। सड़क निर्माण से लेकर संचार सुविधाओं के विस्तार तक हर प्रयास का हिंसक विरोध किया जाता था। कई बार निर्माण सामग्री को जला दिया जाता था, ठेकेदारों को धमकाकर भगा दिया जाता था और विकास कार्यों को रोकने की कोशिश की जाती थी। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। बीते वर्षों में हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया, हजारों मोबाइल टावर स्थापित किए गए और दूरस्थ गांवों तक संचार सुविधाएं पहुंचाई गईं। बैंकिंग सेवाओं, डाक सेवाओं और वित्तीय समावेशन के माध्यम से लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन केवल आधारभूत संरचनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में विश्वास और अवसरों का विस्तार है।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल बम, बंदूक और गोली के सहारे नहीं लड़ी गई। सरकार ने सुरक्षा के साथ–साथ जनसामान्य की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने पर भी समान रूप से ध्यान दिया। शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, गरीबों को अधिकार दिलाने और लोकतंत्र के प्रति विश्वास मजबूत करने के निरंतर प्रयास किए गए। इसी का परिणाम है कि आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आमजन का भरोसा लोकतांत्रिक व्यवस्था और विकास की प्रक्रिया में बढ़ा है। उन्होंने बस्तर का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां कभी आतंक और हिंसा का माहौल था, वहां आज युवाओं की ऊर्जा खेल और प्रतिभा के माध्यम से सामने आ रही है। बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों में लाखों युवाओं की भागीदारी इस परिवर्तन का सशक्त उदाहरण है। यह दर्शाता है कि अब वहां के युवा हिंसा के रास्ते को नहीं, बल्कि अवसर, शिक्षा, खेल और विकास के मार्ग को अपना रहे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशन फर्स्ट संकल्प, दूरदर्शी नेतृत्व और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस ने बस्तर सहित पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कभी नक्सलवाद का आतंक था, वहां आज विकास का आत्मविश्वास दिखाई देता है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बैंकिंग और जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच ने लोगों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित रणनीति, सुरक्षा बलों की वीरता तथा स्थानीय जनता के सहयोग से नक्सलवाद का अध्याय अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज बस्तर की पहचान हिंसा नहीं, बल्कि विकास, जनभागीदारी, खेल, पर्यटन और नई संभावनाओं से बन रही है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन और अंत्योदय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विकास और सुशासन का राष्ट्रीय मॉडल बनेगा तथा बस्तर देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में अपनी पहचान स्थापित करेगा।

कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद के बड़े फैसले : ग्रामीण रोजगार, आजीविका और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने तीन अहम योजनाओं को मिली मंजूरी

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, सशक्तीकरण, विभागीय योजनाओं के अभिसरण और डिजिटल सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी–जी राम जी योजना छत्तीसगढ़ के प्रारूप का अनुमोदन किया है।

भारत सरकार के अधिनियम, 2025 के अनुरूप लागू की जा रही इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण, आजीविकामूलक परिसंपत्तियों के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत आधारित समेकित विकास, विभागीय योजनाओं के अभिसरण तथा पीएम गति शक्ति से समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। विकास कार्यों की बेहतर कार्ययोजना एवं निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करते हुए पारदर्शिता, सुशासन एवं जवाबदेही को सुदृढ़ किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र एवं राज्य के व्यय का अनुपात 60:40 रहेगा तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राज्य बजट में 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सृजन केंद्र (हथकरघा, बुनाई–सिलाई, हस्तशिल्प आदि), प्रसंस्करण इकाइयां (दलहन, तिलहन, राइस मिल, डेयरी आदि), सेवा केंद्र (कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, कृषि उपकरण मरम्मत, अटल डिजिटल केंद्र आदि), विपणन केंद्र तथा आपूर्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

इस योजना का उद्देश्य उपलब्ध अधोसंरचना और मशीनरी का बेहतर उपयोग करते हुए स्थानीय उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा और विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल एजेंसी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। अटल आजीविका समृद्धि हाट के माध्यम से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सेवा व्यवसाय, डिजिटल तकनीक, हरित ऊर्जा तथा ग्रामीण बाजारों को नई गति मिलेगी और प्रदेश की ग्रामीण आजीविका को मजबूत आधार प्राप्त होगा।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति (CG-CBG Policy), 2026 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट एवं अन्य जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कर उन्हें स्वच्छ गैसीय ईंधन कम्प्रेस्ड बायोगैस में परिवर्तित किया जाएगा। इस नीति से अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जैव उर्वरक उत्पादन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अनुसार राज्य में लगभग 5 लाख टन प्रतिवर्ष उइ्रऋउत्पादन की संभावना है। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को राज्य नोडल एजेंसी तथा ऊर्जा विभाग को आवश्यक दिशा–निर्देश और प्रशासनिक आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

रावघाट में पहाड़ काटकर बनी सड़क से वन विभाग बेखबर, बिना अनुमति पेड़ों की कटाई

एसडीओ बोले, बीएसपी ने नहीं ली मंजूरी, डीएफओ ने जांच टीम गठित की

नई दृष्टिबिंदु भिलाई/ कांकेर

रावघाट खदान क्षेत्र में लौह अयस्क परिवहन के लिए पहाड़ काटकर सड़क बनाने और बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि सड़क निर्माण की जानकारी वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड से लेकर एसडीओ स्तर तक किसी को नहीं है। वन विभाग का कहना है कि भिलाई स्टील प्लांट ने सड़क निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए वनमंडलाधिकारी ने जांच टीम गठित कर दी है।

ब्लॉक–ए से डंप तक बनाई गई सड़क

जानकारी के अनुसार रावघाट में लौह अयस्क उत्खनन के लिए बीएसपी को जमीन आवंटित है। आरोप है कि ब्लॉक–ए से डंप स्थल तक अयस्क ले जाने के लिए पहाड़ काटकर सड़क बनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए। सड़क कब बनी और पेड़ किसने काटे, इसकी जानकारी मैदानी अमले के पास भी नहीं है। कटे पेड़ों की लकड़ी कहां गई, इसका भी जवाब विभाग के पास नहीं है। केसीसीएल के सुपरवाईजर चक्रधर मोहंती ने बताया कि कंपनी को जिम्मेदारी मिलने से पहले ही पहाड़ काटकर कच्चा रोड बना हुआ था। हमने सिर्फ डामरीकरण के लिए एनसी नाहर को काम दिया है। पहाड़ और पेड़ किसने काटे, यह कंपनी के संज्ञान में नहीं है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क इसी महीने बनाई गई है।

ले–आउट की मंजूरी जरूरी

जानकारों के अनुसार रावघाट का पूरा माइनिंग लीज एरिया 2028.797 हेक्टेयर वन भूमि है। डायवर्टेड लैंड में भी किसी निर्माण के लिए वन विभाग से अलग से अनुमति या ले–आउट की मंजूरी लेना अनिवार्य है।

अंतागढ़ के एसडीओ विजय चंद्रवंशी ने कहा कि फोटो में दिख रही सड़क बनाने के लिए बीएसपी ने कोई परमीशन नहीं ली है। शिकायत मिलने पर जांच जारी है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

डीएफओ ने बनाई जांच टीम

वनमंडलाधिकारी ऋषभ जैन ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित की है। टीम सड़क निर्माण, पेड़ों की कटाई और लकड़ी की स्थिति सहित सभी पहलुओं की जांच करेगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि घने जंगलों के बीच इतनी बड़ी गतिविधि का वन विभाग को समय पर पता नहीं चलना कई सवाल खड़े करता है।

एएसपी हरीश यादव को अंग्रेजी साहित्य में मिली पीएचडी की उपाधि

वर्ड्सवर्थ और पंत के काव्य पर किया तुलनात्मक शोध, 10 साल की मेहनत लाई रंग

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

जिले में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर ने अंग्रेजी साहित्य में विद्या वाचस्पति यानी पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। उन्होंने रोमांटिकवाद और छायावाद के परिप्रेक्ष्य में विलियम वड्र्सवर्थ एवं सुमित्रानंदन पंत का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर शोध पूरा किया। एएसपी हरीश यादव का शोध अंग्रेजी के रोमांटिक कवि विलियम वड्र्सवर्थ और हिंदी के छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन है। शोध में रोमांटिकवाद और छायावाद की मूल अवधारणाओं, प्रकृति चित्रण, मानवीय संवेदनाओं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और काव्यगत विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन किया गया है। यह हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के वैचारिक साम्य को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

10 साल में पूरा हुआ शोध

इस शोध को पूरा करने में करीब 10 साल का समय लगा। इस दौरान एएसपी हरीश यादव ने पुलिस और प्रशासनिक दायित्व निभाते हुए अध्ययन, अनुसंधान और लेखन जारी रखा। उन्होंने शोध निदेशक डॉ. ए.के. सिंह, पूर्व शोध निदेशक डॉ. यू.एन. कुर्रे, डॉ. सुनीता तिवारी और डॉ. बिंदा शर्मा के मार्गदर्शन में काम किया। अपनी उपलब्धि पर एएसपी हरीश यादव ने कुलपति डॉ. ललित पटेरिया, पूर्व कुलपति डॉ. ए.डी.एन. बाजपेयी, कुलसचिव तारनिष गौतम, कुलसचिव तरुण धर दिवान और विश्वविद्यालय परिवार का आभार जताया।

डीआईजी ने दी बधाई

उपाधि मिलने की खबर से पुलिस विभाग में खुशी का माहौल रहा। पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू सहित जिले के अधिकारियों और कमर्चारियों ने उन्हें बधाई दी। डीएसपी कौशिल्या साहू, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली सोनल ग्वाला, साइबर सेल प्रभारी मयंक मिश्रा, रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, एसपी कार्यालय स्टाफ और जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों ने मिठाई खिलाकर सम्मानित किया।

बीएसपी प्रवर्तन विभाग का अतिक्रमण विरोधी अभियान

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रवर्तन विभाग ने टाउनशिप में स्वच्छता, यातायात सुगमता और सड़क सुरक्षा के लिए सोमवार को विशेष अभियान चलाया। इस दौरान सेक्टर–6 मार्केट चौक और आसपास के क्षेत्रों में अनाधिकृत कब्जे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अभियान के तहत सेक्टर–6 मार्केट चौक के पास सड़क किनारे सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों का अतिक्रमण हटवाया गया। यहां से छह अस्थायी शेड भी हटाए गए। संबंधित लोगों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में सड़क तक सामग्री न फैलाएं और सार्वजनिक मार्ग बाधित न करें।

अनफिट ब्लॉक की बिजली काटी

स्ट्रीट–एवेन्यू सी स्थित अनफिट ब्लॉक में अवैध कब्जे से मार्ग संकरा हो रहा था। पूर्व में समझाइश के बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर नगर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के सहयोग से अवैध बिजली कनेक्शन काट दिया गया। कब्जाधारियों को जल्द कब्जा खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित कार्यदल को ब्लॉक के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के लिए भी निर्देश दिए गए।

ठेले वालों को दी गई चेतावनी

सेंट्रल एवेन्यू से सेक्टर–6 मार्केट जाने वाले मार्ग और चौक क्षेत्र में दिन में ठेले खड़े करने वालों पर भी कार्रवाई हुई। ठेले हटवाए गए और चेतावनी दी गई कि दोबारा सार्वजनिक मार्गो पर ठेले छोड़ने पर संपदा न्यायालय के माध्यम से जब्ती की जाएगी।

अन्य क्षेत्रों में भी चलेगा अभियान

प्रवर्तन विभाग ने बताया कि टाउनशिप के अन्य प्रमुख चौकों और मुख्य मार्गो पर भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी। नागरिकों से अपील की गई है कि सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमण और अनाधिकृत ठेले स्वेच्छा से हटा लें। यह अभियान सहायक महाप्रबंधक प्रवर्तन विभाग रेमी थॉमस के नेतृत्व में चलाया गया। टीम में उप प्रबंधक मुकुंद दास मानिकपुरी, सहायक प्रबंधक देवानंद चौहान, संपदा निरीक्षक अजय मिश्रा, राममूर्ति, भगवान, राम और महिला व पुरुष सुरक्षा कर्मी शामिल रहे।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में रायपुर की अदालत ने आरोपी मनोज महिलांग को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। थाना सिविल लाइन में 2025 में दर्ज अपराध क्रमांक 264/2025 में पुलिस की त्वरित जांच और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला आया है। पुलिस ने मामले में धारा 64(2)(एम), 115(2), 351(2) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर निर्धारित समय में न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सिविल लाइन पुलिस ने नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में शून्य सहिष्णुता की नीति के तहत कार्रवाई की। पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी गई और सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन कर न्याय दिलाया गया। रायपुर पुलिस ने कहा कि यह फैसला बाल अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है। बच्चों के विरुद्ध किसी भी अपराध की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।

महिलाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण : राजमिस्त्री बनकर गढ़ रहीं अपने सपनों का भविष्य

कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में प्रेरणादायक पहल : मजबूत घरों के साथ मजबूत होगा महिलाओं का आत्मविश्वास

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में ग्रामीण महिलाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में ग्राम बठेना, जनपद पंचायत पाटन में एक प्रेरणादायक पहल की जा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), दुर्ग द्वारा संचालित 30 दिवसीय रूरल मेसन (राजमिस्त्री) प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों के द्वार खोल रहा है।

ग्राम बठेना में आयोजित इस प्रशिक्षण में 35 महिलाएं भाग ले रही हैं। यह प्रशिक्षण केवल भवन निर्माण की तकनीक सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास

और आर्थिक सशक्तिकरण की नई राह भी दिखा रहा है। जो महिलाएं कभी निर्माण कार्य को पुरुषों का क्षेत्र मानती थीं, वे आज राजमिस्त्री बनने का प्रशिक्षण लेकर अपने सपनों को नई उड़ान दे रही हैं।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को नींव निर्माण, दीवार निर्माण की वैज्ञानिक तकनीक, छत ढलाई, प्लास्टर, फ्लोरिंग, फिनिशिंग तथा निर्माण सामग्री के सही अनुपात और उपयोग की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। आधुनिक निर्माण तकनीकों के साथ सुरक्षा मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इससे न केवल बेहतर निर्माण कार्य सुनिश्चित होगा, बल्कि सामग्री की अनावश्यक बर्बादी को भी रोका जा सकेगा।

इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर सुश्री अनिता चारभे प्रतिभागियों को तकनीकी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क ड्रेस, टूल किट एवं भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण एवं टिकाऊ आवास निर्माण सुनिश्चित करने में प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य भी कर रहे हैं।

कौशल विकास के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए अवसर प्राप्त कर सकेंगी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। एक ओर जहां प्रशिक्षित महिला राजमिस्त्री प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों को अधिक मजबूत, सुरक्षित और टिकाऊ बनाने में योगदान देंगी, वहीं दूसरी ओर उनके आत्मविश्वास और सामाजिक भागीदारी में भी वृद्धि होगी। आज ये महिलाएं केवल राजमिस्त्री का प्रशिक्षण नहीं ले रहीं, बल्कि अपने भविष्य की मजबूत नींव भी रख रही हैं।

खास खबर

खेलगांव खम्हरिया में स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि का किया गया सीमांकन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

संभाग स्तरीय बहुउद्देशीय स्टेडियम बनने से खेल प्रतिभाओं को मिलेगा अवसर

कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार खेलगांव खम्हरिया (विकासखंड व जिला-दुर्ग) में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के नाम आबंटित 16 एकड़ शासकीय भूमि का सीमांकन कर चिन्हांकित कर लिया गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक से मिली जानकारी के अनुसार, तहसीलदार वसुमित्र दीवान के नेतृत्व में राजस्व विभाग के आरआई घनश्याम चंद्राकर, पटवारी विवेक देवांगन व अन्य टीम, तथा लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर वायके सोनवानी व श्रीमती सुस्मिता चंद्राकर द्वारा चूना और अन्य उपकरणों से भूमि के चारों ओर निशान लगाया गया। उतई थाना टीआई अनिल पटेल के नेतृत्व में 10 पुरुष और 10 महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के कारण यह प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

इस दौरान खेल विभाग के प्रशिक्षक भूपेन्द्र हिरवानी, खम्हरिया सरपंच श्रीमती दुलारी देशलहरे, उपसरपंच टीकाराम साहू, खेल प्रशिक्षक बालक दास डहरे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर (केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त, उपाध्यक्ष छग राज्य ग्रामीण विकास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण) के विशेष प्रयासों से यहाँ संभाग स्तरीय बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हो चुकी है, जिसमें से प्रथम किश्त के रूप में 4 करोड़ रुपये मार्च 2026 में निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग को दिए जा चुके हैं। इस स्टेडियम में 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, सीटिंग गैलरी, इंडोर स्टेडियम (बैडमिंटन कोर्ट) और प्रशासनिक भवन का निर्माण शामिल है, जिससे दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, रिसाली निगम, नगर पंचायत उतई और भिलाई निगम सहित पूरे संभाग के खिलाड़ियों को सीधा लाभ मिलेगा।

राष्ट्रीय शिविर से लौटे छत्तीसगढ़ के 23 आर्य वीर और 26 आर्य वीरांगनाओ का हुआ सम्मान

दुर्ग। राष्ट्रीय शिविर आर्य वीर एवं वीरांगना दल में आर्य वीर एवं वीरांगना दल छत्तीसगढ़ से कुल 23 आर्य वीर एवं 26 आर्य वीरांगना ने भाग लिया जिसमें राष्ट्रीयस्तर में ओम कुमार ने प्रथम स्थान, संदेश आर्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया एवं वीरांगना में भूमिका आर्या ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर सम्मानित अतिथि डॉ आर एस नायक , श्रीमति डॉक्टर मानसी गुलाटी,साक्षी आर्या जी एवं सम्मानित आचार्य जगबंधु की उपस्थिति रही। द्वितीय सत्र में नियमित शाखा क्यों आवश्यक है और कौन कौन आर्य वीर एवं वीरांगना अपने अपने क्षेत्र में शाखा लगाएंगे इसका संकल्प लिया गया। इसकी अध्यक्षता कृष्णमूर्ति आर्य एवं हिमांशु आर्य द्वारा हुई। तीसरे सत्र में शाखा प्रशिक्षण शिविर लगाया गया जिसमें पूरे प्रांत के आर्य वीर वीरांगनाओं को शाखा लगने का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें प्रत्येक वीर वीरांगनाओं द्वारा सामने की ओर आकर भिन्न भिन्न अभ्यास कराया गया। आचार्य अंकित शर्मा के द्वारा बौद्धिक एवं भाई नंदलाल जी द्वारा एक ओजस्वी गीत का अभ्यास कराया गया। तृतीय सत्र की अध्यक्षता व्यायाम शिक्षिका कविता आर्या, भूमिका आर्या प्रेरणा आर्या द्वारा हुई एवं अंत में समर्पित सदस्य आर्य वीर तुषार जी का सम्मान किया गया।

आलिमो ने उठाई आवाज- मुहर्रम और तमाम जुलूस में बंद हो डीजे और शोर-शराबा

बैठक में शामिल हुए दुर्ग-भिलाई की तमाम मस्जिदों के इमाम और आलिम

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग-भिलाई

भिलाई-दुर्ग व आसपास की तमाम मस्जिदों के इमामों और आलिमो की एक अहम बैठक रविवार 21 जून को अशरफी मस्जिद, रूआबांधा बस्ती में रखी गई। अशरफी मस्जिद व मदरसा के सदर सैयद अली के संयोजन में हुई इस बैठक में 10 मुहर्रम के जुलूस के दौरान डीजे, शोर-शराबा, बेपदर्गी और दूसरी गलत रस्मों को रोकने के लिए एक कार्य योजना (रोडमैप) तैयार करने पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद आलिमों ने फिक्र जाहिर करते हुए कहा कि डीजे और अत्यधिक तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम केवल ध्वनि प्रदूषण ही नहीं फैलाते, बल्कि लोगों की सेहत, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था और सार्वजनिक शांति के लिए भी गंभीर खतरा बनते हैं।

बैठक में शामिल उलेमा, हुफ्फाज और इमामों ने इस बात पर जोर दिया कि मुहर्रम जैसे पाक महीने में अमन, संजीदगी और दीन की सही समझ को बढ़ावा दिया जाए। सभी ने मांग की कि शादी, मजहबी जुलूस और दूसरे तमाम सामाजिक आयोजनों में डीजे और बेहद तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम के उपयोग को पूरी तरह बंद किया जाए, ताकि समाज में अमन और भाईचारा कायम रहे। बैठक के आखिर में आलिमों ने प्रशासन से डीजे और अनावश्यक शोर-शराबे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग की।

बैठक में आलिमों ने यह भी साफ किया कि ताजिया यानी हुबहू रौजा-ए-हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नकल बनाकर बरकत की नीयत से रखना अपने आप में प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि यह हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और वाक़ि या-ए-कबर्ला की याद ताजा करने का एक जरिया है। लेकिन ताजिया बनाकर उसे मिट्टी में दबा देना या पानी में बहा देना माल की बर्बादी और बेअदबी है। इसलिए ताजिए के नाम पर होने वाली गलत रस्में, गैर-शरई काम, शोर-शराबा, ढोल-ताशे, महिला-पुरुषों का गैरजरूरी मेल, बेपदर्गी और दूसरे गैर मुनासिब अमल किसी भी हाल में मंजूर

नहीं किए जा सकते, क्योंकि इससे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के असल पैगाम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

आलिमों ने कहा कि अगर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत का इजहार करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका खिदमते खल्क (मानव सेवा) है। उनके नाम पर जरूरतमंदों-मरीजों की मदद की जाए और गरीब बेटियों के शादियों में सहयोग किया जाए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि मुहर्रम के जुलूस अमन, अनुशासन और आपसी सम्मान के साथ निकाले जाएं। जुलूस के दौरान या उसके बाद फैलने वाली गंदगी की सफाई का खास इंतजाम किया जाए, जिससे समाज में सकारात्मक संदेश जाए कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मानने वाले केवल दावे नहीं करते, बल्कि खिदमत, तालीम और सफाई में भी मिसाल पेश करते हैं।

इस अहम बैठक में मुफ्ती जलालुद्दीन रजवी-हाउसिंग बोर्ड, मौलाना इकबाल अंजुम अशरफी-सेक्टर 6, मुफ्ती कलीम अशरफ रजवी कैंप 2, मुफ्ती जामी क़मर अजहरी-जोन 3, मुफ्ती सलीम रजाझइमाम जामा मस्जिद, दुर्ग, मौलाना अमीर अहमद क़ादरी- फरीदिया मस्जिद, मुफ्ती मुहम्मद शाहिद अली मिस्बाही-रुआबांधा, मौलाना शहाबुद्दीन अशरफी-दुर्ग, मुफ्ती माशाअल्लाह-मक्का मस्जिद, फरीद नगर, मुफ्ती फैजान रजा मिस्बाही-बोरसी, क़ारी सनाउल्लाह रजवी-रिसाली, क़ारी उमर फारूक अशरफी-रुआबांधा, क़ारी अब्दुल क़य्यूम-खुर्सीपार 3, हाफिज क़ासिम-रायपुर नाका, दुर्ग, हाफिज इसराफिल-हुडको मस्जिद, क़ारी इरफान-मदरसा अशरफिया, हाफि ज मुहम्मद शमशीर अली अशरफी-रुआबांधा, हाफिज जमील रजा-मरौदा, हाफिज जीशान रजा-मरौदा, हाफिज जुहूर अशरफी-मरौदा, हाफिज शहादत अशरफी-मरौदा, हाफिज ग़ुलाम रजा-नूरी मस्जिद, फरीद नगर, हाफिज मजहर अली-बोरसी, मौलाना मक़सूद-कैंप 1, क़ारी जमील-कैंप 1, हाफि ज मक़सूद रजा-सेक्टर 8, हाफिज शमशीर-केलाबाड़ी, हाफिज रफीउल्लाह-जामुल, हाफि ज शराफत-नूरी मस्जिद, फरीद नगर, मौलाना इलियास मिस्बाही-अशरफिया, दुर्ग, मौलवी इकरामुद्दीन अशरफी-रुआबांधा, हाफिज अब्दुल करीम-फरीद नगर, मुहम्मद रफीक़-कैंप 2, हाफिज अकबर, हाफिज तारिक़-भिलाई, हाफिज असरार-जोन 1,हाफि ज नसीम-जोन 3, हाफिज क़ुरबान- रायपुर नाका, हाफिज नसीमझभिलाई 3, हाफिज एहसान-अशरफि या, दुर्ग, हाफिज इस्माईल-कुरुद, हाफिज मुहम्मद आसिफ-कुरुद, हाफिज नोमान रजा और मदरसा ताजुल उलूम रुआबांधा भिलाई के मैनेजर सैयद अफताबुर्रब सहित दीगर हजरात शामिल हुए।

संजय गांधी की 46वीं पुण्यतिथि पर अरुण वोरा ने दी श्रद्धांजलि

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

स्व. संजय गांधी की 46वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक अरुण वोरा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके राष्ट्र निर्माण संबंधी विचारों को स्मरण किया। संजय गांधी का निधन 23 जून 1980 को हुआ था।

अरुण वोरा ने कहा कि संजय गांधी उन दूरदर्शी नेताओं में थे जिन्होंने 1970 के दशक में ही भारत के सामने आने वाली अनेक चुनौतियों को पहचान लिया था। जनसंख्या संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और सामाजिक सुधार जैसे विषय आज राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ बन चुके हैं, जबकि संजय गांधी ने इन मुद्दों की आवश्यकता को दशकों पहले ही समझ लिया था।

उन्होंने कहा कि युवाशक्ति पर संजय गांधी का अटूट विश्वास था तथा उनका प्रसिद्ध पंचसूत्रीय कार्यक्रम सशक्त भारत के निर्माण का एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, साक्षरता, दहेज उन्मूलन और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों को उन्होंने जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया।

वोरा ने कहा कि संजय गांधी की दूरदृष्टि, ऊर्जा और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण आज भी प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने उनकी पुण्य स्मृति को नमन करते हुए कहा कि देश के विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए उनके अनेक विचार आज भी प्रासंगिक हैं।

अरुण वोरा ने स्व संजय गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व महापौर आर.एन. वर्मा, राजकुमार पाली, सुमित घोष, पप्पू श्रीवास्तव, मनोज सिन्हा, लक्की नागेश, आनंद कपूर ताम्रकार, दुष्यंत देवांगन, अशोक मेहरा, सुधीर चंदेल, राहुल अग्रवाल, प्रीतम देशमुख सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे।

आयुक्त ने परामर्शदात्री समिति की बैठक में विभिन्न मांगों पर की चर्चा और कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण व नियमित भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने पर दिया जोर

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

एनपीएस, वेतन वृद्धि और अवकाश संबंधी मुद्दों पर विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश

नगर पालिक निगम दुर्ग के आयुक्त सुमित अग्रवाल के चेम्बर में आज स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय मिश्रा, महामंत्री अनिल सिंह सहित संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान ईश्वर वर्मा, शशिकांत यादव, शानू कोठारी, रेखा कुर्रे, हेमलता वर्मा एवं किरण अग्रवाल भी मौजूद रहे।

कर्मचारी संघ की ओर से बताया गया कि लगातार कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से निगम में कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है, जिसके कारण कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए शासन को अवगत कराते हुए नियमित भर्ती हेतु प्रस्ताव भेजने की मांग रखी गई। बैठक में कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने के आधार पर वेतन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने की कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। कर्मचारी

प्रतिनिधियों ने ऐसे आदेशों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

इसके अलावा निगम परिसर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने, शासकीय अवकाश के दिनों में कार्य लेने की स्थिति में नियमानुसार वेतन अथवा प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने तथा तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के परिवारों को मृत्यु की स्थिति में उपादान एवं परिवार पेंशन का लाभ समय पर उपलब्ध कराने, एनपीएस/जीपीएस की राशि नियमित रूप से जमा कराने तथा खातों के संधारण एवं जमा राशि की जानकारी शासन स्तर से प्राप्त करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। आयुक्त सुमित अग्रवाल ने सभी विषयों पर आवश्यक परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की बात कही।

शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी दें प्राथमिकता-एसएसपी अग्रवाल

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

ब्रह्माकुमारीज के सुरक्षा प्रभाग की रजत जयंती पर आत्म सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण विषयक कार्यक्रम आयोजित

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के सुरक्षा सेवा प्रभाग के सफलतापूर्वक 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बघेरा स्थित आनंद सरोवर परिसर के कमला दीदी सभागार में आत्म सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण विषय पर प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पुलिस बल, एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स), बटालियन, नगर सैनिक तथा एनसीसी के 700 से अधिक जवानों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसएसपी दुर्ग विजय अग्रवाल, एसपी एसटीएफ त्रिलोक बंसल, कमांडेंट होमगार्ड नागेंद्र सिंह, डीएसपी चंद्रप्रकाश तिवारी, रक्षा मंत्रालय के जे.डब्ल्यू.एम. मिसाइल एवं रॉकेट विभाग के वैज्ञानिक अधिकारी बी.के. पुरुषोत्तम, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ बी.के. प्रिया, माउंट आबू से पधारे बी.के. शैलेन्द्र, ब्रह्माकुमारीज दुर्ग केंद्र की संचालिका रीटा दीदी एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका रूपाली दीदी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर बी.के. शैलेन्द्र ने सुरक्षा सेवा प्रभाग की 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और मूल्यनिष्ठ समाज निर्माण की दिशा में किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2001 से प्रारंभ हुए इस प्रभाग ने देशभर में राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रशिक्षण शिविर, सेमीनार और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित कर सेना, पुलिस एवं सुरक्षा बलों के हजारों अधिकारियों और जवानों को लाभान्वित किया है।

ब्रह्माकुमारीज दुर्ग की संचालिका रीटा दीदी ने

स्वागत उद्बोधन में कहा कि देश और समाज की सुरक्षा में लगे जवानों के जीवन में तनाव स्वाभाविक रूप से आता है, ऐसे में आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति प्रदान करना समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी को व्यसन एवं बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया।

एसएसपी विजय अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस और सुरक्षा सेवाओं में कार्यरत लोगों को लगातार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देना आवश्यक है।

मुख्य वक्ता बी.के. पुरुषोत्तम ने कहा कि मानव स्वयं में एक अद्भुत सुपर कंप्यूटर है और व्यक्ति के संकल्प ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। उन्होंने सकारात्मक सोच और खुशियां बांटने का संदेश दिया।

एसपी एसटीएफ त्रिलोक बंसल ने कहा कि आनंद सरोवर परिसर में आने पर सदैव शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। उन्होंने कार्यक्रम से प्राप्त सीख को जीवन एवं परिवार में अपनाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका रूपाली दीदी एवं बी.के. प्रिया ने उपस्थित जवानों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया तथा सकारात्मक चिंतन के माध्यम से तनावमुक्त जीवन जीने के उपाय बताए। कार्यक्रम का संचालन माउंट आबू से पधारे ब्रह्माकुमार शैलेन्द्र भाई ने किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्माकुमारीज के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में सुरक्षा प्रभाग से जुड़े लोगों के लिए वर्ष में दो बार विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें संस्था के किसी भी केंद्र के माध्यम से भाग लिया जा सकता है।

निर्माण व जन सुविधाएं विकसित करने के कार्यों को गति देने सक्रियता से करें मॉनिटरिंग - शंगीता आर

नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव ने नोडल अधिकारियों की ली बैठक, समस्याओं का हल निकालकर काम आगे बढ़ाने के दिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने नगरीय निकायों के कार्यों की मॉनिटरिंग व समन्वय के लिए जिलेवार नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर उनके कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में सभी नोडल अधिकारियों को नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में निर्माण और जन सुविधाएं विकसित करने के कार्यों को गति देने सक्रियता एवं गंभीरता से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने निकायों की समस्याओं का हल निकालकर विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों में मैदानी निरीक्षण के दौरान वहां की जरूरतों और व्यवस्थाओं का आकलन भी करने को कहा।

नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने बैठक में नोडल अधिकारियों से उनके नगरीय निकायों के भ्रमण और बैठकों का फीडबैक लेकर निकायों में कार्यों की वस्तुस्थिति जानी। उन्होंने कहा कि निकायों में कार्यों के निरीक्षण के लिए पूरी तैयारी से जाएं। विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों में कितनी राशि जारी की गई है, इसकी भी जानकारी रखें। उन्होंने निकायों में प्रगतिरत निर्माण कार्यों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की भी हर महीने समीक्षा करने के निर्देश दिए।

श्रीमती शंगीता आर. ने नोडल अधिकारियों को आबंटित जिले के आय-व्यय की स्थिति पर भी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो निकाय खुद की आय से अपनी सभी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने निकायों में लक्ष्य निर्धारित कर वाडर्वार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को सेचुरेट करने को कहा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक आर. एक्का, उप सचिव भागवत जायसवाल, राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ शशांक पाण्डेय, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता राजेश शर्मा भी बैठक में मौजूद थे।

शहरी विकास योजनाओं की निगरानी को और सशक्त करने नोडल अधिकारी कर रहे स्थल निरीक्षण, अब तक 103 निकायों का निरीक्षण कर चुके नोडल अधिकारी

नगरीय प्रशासन विभाग ने विकास कार्यों और योजनाओं की जमीनी स्तर पर निगरानी को सुदृढ़ करने सभी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को अपने-अपने आबंटित जिलों के नगरीय निकायों के नियमित भ्रमण के निर्देश दिए हैं। विगत 6 जून को एक साथ सभी नोडल अधिकारियों ने अपने जिलों में पहुंचकर योजनाओं की प्रगति, चुनौतियों और क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन किया। विभाग की इस पहल का उद्देश्य योजनाओं की प्रभावी निगरानी, समस्याओं का त्वरित समाधान तथा मैदानी स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। अलग-अलग जिलों के नोडल अधिकारी अब तक राज्य के 194 नगरीय निकायों में से 103 में मैदानी निरीक्षण के लिए जा चुके हैं।

खास खबर

भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के सशक्त प्रहरी है डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में प्रख्यात शिक्षाविद्, भारत के प्रथम उद्योग मंत्री, राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के सशक्त प्रहरी थे। उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए समर्पित किया। उनके विचार, संघर्ष और त्याग भारतीय लोकतंत्र एवं राष्ट्रवादी चिंतन की अमूल्य धरोहर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने देश की राजनीति को वैचारिक आधार प्रदान किया तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र की अखंडता और सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज भी प्रत्येक देशवासी के लिए प्रेरणास्रोत है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते समय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्श और सिद्धांत हमें निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके विचारों को आत्मसात कर ही हम राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह, राम गर्ग सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

राज्यपाल डेका ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि

वहीं राज्यपाल रमेन डेका ने भी प्रखर राष्ट्रवादी नेता एवं महान शिक्षाविद् डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर लोक भवन में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने डॉ. मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और को सुदृढ़ करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनके विचार और आदर्श आज भी देशवासियों को राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। लोक भवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण पर की जा रही है निरंतर कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / बालोद-रायपुर

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिसके अंतर्गत खनिज विभाग के द्वारा 21 जून 2026 को डौण्डीलोहारा विकासखण्ड का औचक निरीक्षण किया गया। जिला खनि अधिकारी ने बताया कि खनिज विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान 02 स्थानों पर 06 हाईवा एवं 07 हाईवा द्वारा खनिज रेत का अवैध भण्डारण पाया गया। जिसमें दोनों अवैध भण्डारकर्ताओं द्वारा भण्डारित खनिज को जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मौका पंचनामा अनुसार उक्त रेत भण्डारण, भण्डारकर्ताओं द्वारा धमतरी व कांकेर के रेत खदानों से परिवहन एवं भण्डारण किया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी खनिज जांच दल द्वारा खनिज के अवैध परिवहन, उत्खनन व भण्डारणकर्ताओं के विरूध्द निरंतर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कौन से गांव में कितना भू-जल, एनआईटी रायपुर करेगा इसका वैज्ञानिक अध्ययन

ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-धमतरी

जिले में भू-जल स्तर के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर संचालित मोर गाँव मोर पानी अभियान को और अधिक प्रभावी एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले के विकासखंड धमतरी एवं कुरूद को भू-जल दोहन की स्थिति के आधार पर क्रमशः क्रिटिकल एवं सेमी-क्रिटिकल श्रेणी में चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं भू-जल पुनर्भरण के स्थायी समाधान विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), रायपुर के विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तावित किया गया है।

इस अध्ययन के तहत एनआईटी रायपुर की विशेषज्ञ टीम चयनित ग्रामों में उपलब्ध भू-जल की स्थिति, जल स्रोतों की क्षमता, जल स्तर में हो रहे बदलाव तथा वर्षा जल के संरक्षण की संभावनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करेगी। अध्ययन में यह भी आकलन किया जाएगा कि किस गांव में कितना भू-जल उपलब्ध है, जल संरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा किन उपायों से भू-जल स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वे एवं स्पॉट स्टडी के आधार पर जल संरक्षण एवं भू-जल पुनर्भरण के लिए सबसे उपयुक्त संरचनाओं की पहचान की जाएगी।

कलेक्टर अभिनाश मिश्रा द्वारा राज्य स्तर पर प्रेषित प्रस्ताव में अनुरोध किया गया है कि एनआईटी रायपुर के विशेषज्ञ चयनित ग्रामों एवं स्थलों का स्पॉट स्टडी तथा हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वे कर भू-जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपयुक्त संरचनाओं की पहचान करें। साथ ही उनके तकनीकी डिजाइन, संभावित प्रभाव, जल पुनर्भरण क्षमता तथा क्रियान्वयन की कार्ययोजना संबंधी विस्तृत तकनीकी प्रतिवेदन तैयार किया जाए। इस संबंध में एनआईटी रायपुर के सहायक प्राध्यापक डॉ. विकास कुमार विद्यार्थी ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रभावी अनुशंसाओं एवं दीर्घकालिक परिणामों के लिए व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक होगा। उन्होंने अध्ययन कार्य हेतु प्रस्तावित ग्रामों एवं स्थलों की संख्या तथा उनका विवरण उपलब्ध उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि संस्थान द्वारा विस्तृत कार्ययोजना, तकनीकी प्रस्ताव तथा आवश्यक वित्तीय प्रावधान का आकलन तैयार किया जा सकेगा।

राज्य मनरेगा आयुक्त कार्यालय द्वारा भी जिला प्रशासन से धमतरी एवं कुरूद विकासखंड के उन ग्रामों एवं स्थलों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है, जहां अध्ययन कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। जानकारी प्राप्त होने के उपरांत एनआईटी रायपुर द्वारा अध्ययन की रूपरेखा, समय-सीमा, तकनीकी आवश्यकताओं एवं व्यय संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर मनरेगा तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत जल संरक्षण एवं भू-जल पुनर्भरण संबंधी कार्यों को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां प्रतिवर्ष जल संकट या भू-जल की कमी की स्थिति बनी रहती है। वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अनुरूप जल संरचनाओं का निर्माण एवं सुधार कर दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मोर गाँव मोर पानी अभियान का उद्देश्य वर्षा जल के अधिकतम संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण तथा जल स्रोतों के दीर्घकालिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर तैयार होने वाली कार्ययोजना से जल संरक्षण संरचनाओं की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। इससे भू-जल स्तर में सुधार, सिंचाई एवं पेयजल उपलब्धता में वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

महिला आयोग की सुनवाई में छह वर्ष से साथ रह रही महिला से विवाह कराने के निर्देश

आयोग के हस्तक्षेप से पत्नी और बच्चों को मिलेगा 20 हजार रुपए मासिक भरण-पोषण

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती प्रियम्वदा सिंह जूदेव ने आज जशपुर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न एवं अन्य प्रकरणों की सुनवाई की। प्रदेश भर में आयोजित सुनवाई में 401 मामलों पर विचार किया गया, जिनमें जशपुर जिले के 10 प्रकरण शामिल रहे।

सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण मामले में आयोग ने छह वर्षों से साथ रह रहे एक युगल के विवाह की प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए। मामले में अनावेदक, जो वर्तमान में सेना में कार्यरत है, ने आवेदिका के साथ लंबे समय से सहजीवन में रहने और उनसे एक पुत्री होने की बात स्वीकार की। आयोग के समक्ष आवेदिका ने एफआईआर दर्ज कराने के बजाय विधिवत विवाह कराने की इच्छा जताई, जिस पर अनावेदक ने सहमति दी। आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दोनों पक्षों के विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ कर दो माह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही अनावेदक को प्रत्येक माह 10 हजार रुपए भरण-पोषण राशि जमा कराने का आदेश दिया गया।

एक अन्य प्रकरण में सीआरपीएफ में पदस्थ कमचारी द्वारा पत्नी और दो बच्चों के भरण-पोषण की उपेक्षा किए जाने की शिकायत पर आयोग ने हस्तक्षेप किया। सुनवाई के दौरान अनावेदक ने अपनी पत्नी एवं बच्चों के लिए प्रतिमाह 20 हजार रुपए भरण-पोषण राशि देने पर सहमति व्यक्त की। आयोग ने संरक्षण अधिकारी को नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में आयोग ने दोनों पक्षों को तहसीलदार के समक्ष सीमांकन कराने और वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार भूमि का कब्जा सुनिश्चित करने की सलाह दी। सीएचसी फरसाबहार में पदस्थ एक स्टाफ नर्स की आवास संबंधी शिकायत पर आयोग ने संबंधित विभाग को आवंटित शासकीय आवास की तत्काल मरम्मत कराने तथा मरम्मत अवधि में नियमानुसार एचआरए प्रदान करने के निर्देश दिए।

सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के लिए 17 श्रद्धालु रवाना, मंत्री चौधरी ने दी शुभकामनाएं

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-रायगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार की तीर्थ यात्रा योजना के तहत रायगढ़ जिले के 17 श्रद्धालु सोमवार को सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के लिए रवाना हुए। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने यात्रियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनकी सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की कामना की।

इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों एवं श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए उन्हें देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन का अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा योजना केवल यात्रा नहीं, बल्कि लोगों की वर्षों पुरानी धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बन रही है।

श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह, जताया सरकार के प्रति आभार

सोमनाथ धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक एवं अन्य कारणों से कई लोगों के लिए देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता, लेकिन इस योजना ने उन्हें पवित्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का अवसर प्रदान किया है। श्रद्धालुओं ने इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया।

आस्था और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ-साथ संस्कृति, परंपरा और धार्मिक आस्था के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। तीर्थ यात्रा जैसी योजनाएं समाज के उन वर्गों तक भी धार्मिक अवसर पहुंचा रही हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में ऐसे तीर्थ स्थलों की यात्रा नहीं कर पाते।

श्रद्धालुओं को दी गई विदाई

यात्रा रवाना होने से पूर्व श्रद्धालुओं का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यात्रियों से संवाद कर उनकी सुविधाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर नगर निगम महापौर जीवर्धन चौहान, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी महेश पटेल सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं श्रद्धालुओं के परिजन उपस्थित रहे। सभी ने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए मंगलमय यात्रा के लिए विदाई दी।

नगर निगम के वार्ड-40 में उद्योग मंत्री देवांगन ने सड़क डामरीकरण का कार्य प्रारंभ कराया

प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी है, तभी से छत्तीसगढ़ राज्य के साथ-साथ हमारे कोरबा में भी विकास को तेज गति व सही दिशा मिली है-महापौर संजूदेवी राजपूत

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-कोरबा

प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने नगर निगम कोरबा के वार्ड क्र. 40 पाड़ीमार वार्ड में सड़क डामरीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत उपस्थित थी। उन्होंने डामरीकरण कार्य के दौरान गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने एवं शीघ्र कार्य को पूर्ण किये जाने के निर्देश मौके पर अधिकारियों को दिये।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अनवरत रूप से किये जा रहे विकास कार्यों की कड़ी में निगम के बालको जोन अंतर्गत वार्ड क्र. 40 पाड़ीमार क्रमांक 01 में 25 लाख रूपए की लागत से राजेश ठाकुर के घर से बरगद चौक होते हुये इंदिरा मार्केट मुख्य मार्ग तक सड़क डामरीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

अब तक निगम क्षेत्र में 1000 करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत

उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस मौके पर अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के आशीर्वाद से विगत ढाई वर्ष के दौरान नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न मदों के अंतर्गत लगभग 1000 करोड़ रूपये के विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें अनेक कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, अनेक प्रगति पर हैं तथा शेष कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहे हैं। उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि निगम क्षेत्र में 15 करोड़ रूपये के सड़क डामरीकरण कार्य कराये जाने हैं, जिसमें अनेक कार्य पूर्ण भी कर लिये गये हैं, जैसे-जैसे डामर की उपलब्धता होती जायेगी, यह कार्य संपादित होंगे। उन्होने आगे कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का तेजी से विकास हो रहा है तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार की दर्जनों जनकल्याणकारी योजनाओं व मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राज्य की विभिन्न योजनाओं से प्रदेश व देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

बिना भेदभाव के हो रहे विकास कार्य

इस अवसर पर महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नगरीय प्रशासन मंत्री व उप मुख्यमंत्री अरूण साव तथा उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के आशीर्वाद से निगम क्षेत्र में व्यापक रूप से विकास कार्य हो रहे हैं तथा सभी 67 वार्डों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी है, तभी से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के साथ-साथ हमारे कोरबा में भी विकास को तेज गति व सही दिशा मिली है, बरसों से व्याप्त समस्याएं दूर हो रही हैं तथा लोगों को आवश्यक सुविधाएं सहज रूप से मुहैया हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें कोरबा की जनता का जो भरपूर आशीर्वाद मिला, उन्होंने हम पर जो विश्वास जताया, वह विश्वास हमेशा बना रहेगा, विश्वास टूटने नहीं दिया जाएगा, इस हेतु हम कृत संकल्पित हैं।

इस अवसर पर एमआईसी सदस्य हितानंद अग्रवाल, सत्येन्द्र दुबे, रजत खुंटे, मंगलराम बंदे, चेतन सिंह मैत्री, चंदादेवी रबारकर, तरूण राठौर के साथ ही दिलेन्द्र यादव, जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, नरेन्द्र पाटनवार, आकाश श्रीवास्तव, मनोज सिंह, जय कुमार राठौर, प्रीति स्वणकार, रेणु प्रसाद, दीपक चन्द्रा, लखन चन्द्रा, हेमलता निर्मलकर, निगम के सहायक अभियंता मोतीलाल बरेठ, अंजूलता तिग्गा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, निगम के अन्य कर्मचारीगण एवं काफी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

संपादकीय

दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है ओलम्पिक

आधुनिक ओलम्पिक खेलों का पहला आयोजन वर्ष 1896 में हुआ था लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इसीलिए 1948 में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस मनाए जाने की शुरूआत हुई। तभी से इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस मनाया जाता है। भारत आधुनिक ओलम्पिक खेलों में 106 वर्ष का सफर पूरा कर रहा है। भारत ने पहली बार वर्ष 1900 में ओलम्पिक में हिस्सा लिया था। तब भारत की ओर से केवल एक एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड को भेजा गया था, जिसने एथलेटिक्स में दो रजत पदक जीते थे।

हालांकि भारत ने अधिकारिक तौर पर पहली बार 1920 में ओलम्पिक खेलों में हिस्सा लिया था। 2024 में पेरिस ओलम्पिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 पदक भारत की झोली में डाले थे जबकि उससे पहले 2021 में टोक्यो ओलम्पिक में भारत 7 पदक जीतने में सफल हुआ था। ओलम्पिक खेलों की शुरूआत करीब 2798 वर्ष पूर्व ग्रीस में जीयस के पुत्र हेराकल्स द्वारा की गई मानी जाती है किन्तु ऐसी धारणा है कि यह खेल उससे भी काफी पहले से ही खेले जाते रहे थे। 776 ईसा पूर्व विधिवत रूप से शुरू हुए ओलम्पिक खेलों का सिलसिला उसके बाद निर्बाध रूप से 393 ई. तक अर्थात 1169 वर्षों तक चलता रहा। इन खेलों के माध्यम से ऐसा प्रदर्शन किया जाता था, जो मानव की शक्ति, गति एवं ऊर्जा का परिचायक माना जाता था। प्राचीन ओलम्पिक खेलों का आयोजन ईश्वर को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता था।

अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस मनाए जाने की शुरूआत 23 जून 1948 को हुई थी। दरअसल आधुनिक ओलम्पिक खेलों का पहला आयोजन तो वर्ष 1896 में हुआ था लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) की स्थापना पियरे द कुबर्तिन द्वारा 23 जून 1894 को की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने थे यूनानी व्यापारी डेमट्रियोस विकेलास। आईओसी का मुख्यालय स्विट्जरलैण्ड के लॉजेन में स्थित है और वतर्मान में दुनियाभर में 205 राष्ट्रीय ओलम्पिक समितियां इसकी सदस्य हैं। आईओसी के स्थापना दिवस 23 जून को ही बाद में अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा प्रतिवर्ष ओलम्पिक दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया। आईओसी द्वारा प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल पर ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेल, शीतकालीन ओलम्पिक खेल और युवा ओलम्पिक खेल का आयोजन किया जाता है। पहला ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक वर्ष 1896 में यूनान के एथेंस में तथा पहला शीतकालीन ओलम्पिक 1924 में फ्रांस के चेमोनिक्स में आयोजित किया गया था। ओलम्पिक दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, जिसमें दो सौ से ज्यादा देश हिस्सा लेते हैं।

फ्रांस के युवा शिक्षाशास्त्री पियरे द कुबर्तिन ने आधुनिक ओलम्पिक खेलों की आधारशिला रखी थी और उनके द्वारा 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति की स्थापना किए जाने के बाद नए रूप में 1896 से आधुनिक ओलम्पिक खेलों का आयोजन शुरू हुआ। उसके बाद ओलम्पिक खेल प्राचीन ओलम्पिक खेलों की ही भांति हर चार वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाने लगे। एक जनवरी 1863 को जन्मे पियरे द कुबर्तिन की उम्र उस वक्त सिर्फ सात साल थी, जब 1870 में फ्रैंच-परसियन लड़ाई में जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। माना जाता है कि उस हार के कुछ वर्षों बाद कुबर्तिन इसका विश्लेषण करने पर इस नतीजे पर पहुंचे कि फ्रांस की हार का कारण उसकी सैन्य कमजोरियां नहीं बल्कि फ्रांसीसी सैनिकों में ताकत की कमी थी। जर्मन, ब्रिटिश और अमेरिकन बच्चों की शिक्षा का अध्ययन करने के बाद कुबर्तिन ने पाया कि उन्हें ताकतवर और हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने में खेलों में उनकी भागीदारी की सबसे प्रमुख भूमिका थी जबकि फ्रांसीसी खेलों में भागीदारी के मामले में काफी पिछड़े थे। उसके बाद कुबर्तिन ने कोशिशें की कि फ्रांसीसियों को किसी भी तरह खेलों के प्रति आकर्षित किया जाए लेकिन उन्हें इन प्रयासों में उसाहजनक सफलता नहीं मिली किन्तु कुबर्तिन अपने इरादों पर दृढ़ थे।

1890 में कुबर्तिन ने यूनियन डेस सोसायटीज फ्रांसीसीज द स्पोर्टस एथलेटिक्स नामक एक खेल संगठन की नींव रखी और उसके दो वर्ष बाद कुबर्तिन के दिमाग में ओलम्पिक खेलों को पुनर्जीवन देने का विचार आया। खेल संगठन की 25 नवम्बर 1892 को पेरिस में हुई एक मीटिंग में उन्होंने इस संबंध में अपने विचार भी रखे किन्तु उनके उस भाषण से कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके दो वर्ष बाद कुबर्तिन ने 9 देशों के कुल 79 डेलीगेट्स की एक मीटिंग आयोजित की। इस मीटिंग में कुबर्तिन ने पूरे उत्साह से ओलम्पिक खेलों की नए सिरे से पुन: शुरूआत करने संबंधी भाषण दिया और इस बार वह लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करने में सफल हुए। कांफ्रैंस में सभी डेलीगेट्स ने एकमत से ओलम्पिक खेल कराए जाने के पक्ष में वोट दिया और तय किया गया कि कुबर्तिन इन खेलों के आयोजन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन करें। उसके बाद ह्यअंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समितिह्न का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में ग्रीस के डेमट्रियोस विकेलास का चयन हुआ। प्रथम ओलम्पिक खेलों के आयोजन के लिए एथेंस को चुना गया और इसकी तैयारियां शुरू हुई। 5 अप्रैल 1896 को प्रथम आधुनिक ओलम्पिक खेलों की शुरूआत हुई। प्रथम आधुनिक ओलम्पिक खेलों का उद्घाटन 5 अप्रैल 1896 को एथेंस (यूनान) में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया। अमेरिका के जेम्स बी. कोनोली को पहले आधुनिक ओलम्पिक खेल में प्रथम ओलम्पिक चैम्पियन बनने का गौरव हासिल है।

पहले ओलम्पिक खेल की प्रतियोगिताओं में महिलाओं के भाग लेने पर प्रतिबंध था किन्तु सन 1900 में दूसरे ओलम्पिक में महिलाओं को भी ओलम्पिक खेलों के जरिये अपनी प्रतिभा का परिचय देने का अवसर मिल गया। प्रथम आधुनिक ओलम्पिक में भाग लेने वाले कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी थे, जो उस वक्त एथेंस में ही पर्यटक के तौर पर पहुंचे हुए थे। 1896 से ओलम्पिक खेलों का आयोजन नियमित होता रहा है लेकिन प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1916, 1940 तथा 1944 के ओलम्पिक आयोजन रद्द करने पड़े थे। यूनान (ग्रीस), ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया तथा फ्रांस ही पांच ऐसे देश हैं, जिन्होंने अब तक हर ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलों में हिस्सा लिया है। ओलम्पिक खेलों के उद्घाटन के समय स्टेडियम में सबसे पहले ग्रीस की टीम प्रवेश करती है। उसके बाद मेजबान देश की भाषानुसार वणर्माला के क्रम से एक-एक करके दूसरे देशों की टीमें स्टेडियम में प्रवेश करती हैं जबकि मेजबान देश की टीम सबके बाद स्टेडियम में पहुंचती है।

गुजरे जमाने के फुटपाथ और छाँव देते दरख़्त

संजय सक्सेना

शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में सड़कों के किनारे बने फुटपाथ और लंबी दूरी के मार्गों के किनारे हरियाली सहित पथिकों को छाया देने वाले वृक्ष अतीत की बात हो गए हैं। फुटपाथ पर दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है तो वृक्ष कहीं मार्ग चौड़ीकरण तो कहीं विकास की भेंट चढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2026 के अपने फैसले में पैदल यात्रियों के फुटपाथ पर सुरक्षित चलने को उनका मौलिक अधिकार करार दिया। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक स्कूल जा रहे पाँच वर्षीय बच्चे की मौत का मुआवजा बढ़ाते हुए यह निर्देश दिया। एक वक्त था जब लखनऊ की हजरतगंज हो या बनारस की गोदौलिया या अन्य छोटे-छोटे शहरों की सड़कों के किनारे चौड़े और साफ फुटपाथ हुआ करते थे। उन पर इमली, नीम और पीपल के घने पेड़ छाया बिछाए खड़े रहते थे। दोपहर की तपती धूप में एक थका-हारा मजदूर उस छाँव में दो पल बैठ लेता था, स्कूल जाते बच्चे उसी फुटपाथ पर बेफिक्र चहलकदमी करते थे और बूढ़े-बुजुर्ग शाम को टहलने निकलते तो सड़क की गाड़ियों का खौफ उन्हें नहीं सताता था। वह भारत अब केवल पुरानी तस्वीरों में दिखता है। आज की हकीकत यह है कि फुटपाथ दुकानों के गोदाम बन चुके हैं, पेड़ विकास की बलिवेदी पर चढ़ चुके हैं और पैदल चलने वाला आम आदमी अपनी ही सड़क पर बेगाना हो गया है।

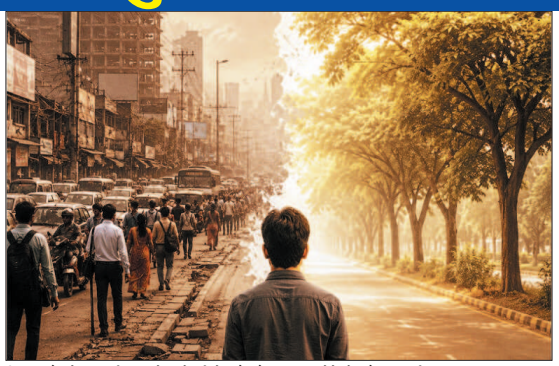

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को अपने फैसले में ऐसा कुछ नहीं कहा जो हमारे संविधान में नहीं लिखा हो, लेकिन सवाल यह है कि कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर कारर्वाई कौन करे। हालत यह है कि पिछले कुछ दशकों में बड़े-बड़े व्यापारियों ने पहले तो फुटपाथ घेरकर अतिक्रमण किया, फिर बाद में उनके अतिक्रमण का दायरा सड़क तक फैल गया। व्यापारी, जिन्हें धन्ना सेठ भी कहा जाता है, सिस्टम को पैसे के बल पर और राजनीतिक दलों को चंदा देकर सबका मुंह बंद कर देते हैं। पूरे प्रदेश में अतिक्रमण का यही हाल है। नगर निगम और एलडीए अक्सर अतिक्रमण के खिलाफ मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन वे बाजारों से अतिक्रमण हटाते हुए कभी नहीं दिखाई देते हैं। भू-माफियाओं की तरफ से मुंह मोड़े रहते हैं। सवाल यह है कि जो अधिकार संविधान में पहले से लिखा था, उसे अदालत को घोषित क्यों करना पड़ा? इसका जवाब हमारे शहरों की उन गलियों में मिलता है जहाँ फुटपाथ पर सब्जी वाले का ठेला है, कपड़े वाले का तिरपाल है, मोबाइल ठीक करने वाले की मेज है और उसके आगे एक ऐसा अँधेरा है जिसमें पैदल चलने वाले के लिए कोई जगह नहीं बची।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक रिटायर होने जा रहे पुलिस के एक बड़े अधिकारी का किस्सा सुनाया था, जिसमें इस अधिकारी ने सीएम को बताया था कि लखनऊ के पॉश इलाके में एक माफिया ने 120 एकड़ जमीन कब्जा रखी है। यदि उसे माफिया से मुक्त करा दिया जाए तो वहाँ राज्य फॉरेंसिक संस्थान खोला जा सकता है। जिसे योगी ने खाली करा लिया, लेकिन न जाने आज भी ऐसी कितनी जमीनें होंगी जो माफियाओं ने कब्जा करके कहीं कॉलोनी बना दी होंगी तो कहीं बस्तियां बसा दी होंगी। मगर अफसोस यह है कि अतिक्रमण के खिलाफ सिर्फ वहीं पर मोर्चा खोला जाता है जहाँ कार्रवाई करके सरकार को खुश किया जा सकता है या फिर ऐसी जगह से अतिक्रमण हटाया जाता है जहाँ अतिक्रमणकारी थोड़ा लाचार और कमजोर होता है।

खैर, बात फुटपाथ की की जाए तो एक समय था जब पैदल यात्री बीच सड़क पर गाड़ियों की चकाचौंध और अंधी दौड़ के साथ धूप और बरसात से बचते हुए आराम से फुटपाथ पर सुरक्षित आता-जाता था। मगर यह सब करीब पचास साल पुरानी बातें हुआ करती थीं। बीते पचास सालों में सरकार ने फुटपाथ के नाम पर पैसा तो खूब लुटाया, लेकिन किसी पैदल चलने वाले राहगीर को इससे फायदा नहीं हुआ। 70 और 80 के दशक में जब शहर छोटे थे और आबादी का दबाव कम था, तब फुटपाथ बनाए गए थे और उन पर पेड़ लगाए गए थे। नगरपालिकाएँ उनकी देखभाल करती थीं। धीरे-धीरे शहर फैलने लगे, आबादी बढ़ने लगी और सड़कों पर वाहनों की तादाद बेतहाशा बढ़ गई। इसी के साथ एक ऐसी व्यवस्था पनपी जिसमें पैसे वाले व्यापारी ने पहले फुटपाथ के कोने में अपना सामान रखा, फिर धीरे-धीरे पूरे फुटपाथ को घेर लिया और बाद में उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने सड़क का एक हिस्सा भी हड़प लिया। इस पूरी प्रक्रिया में नगर निगम के अधिकारी, पुलिस के सिपाही और नेताओं के दलाल सब शामिल रहे। पैसे का लेन-देन होता रहा और अतिक्रमण बढ़ता रहा। मतलब यह है कि यह अतिक्रमण एक दिन में नहीं हुआ। इसकी जड़ें पचास साल पीछे तक जाती हैं।

असली त्रासदी यह है कि सरकारी सिस्टम केवल वहाँ काम करता है जहाँ कमजोर और बेसहारा लोग होते हैं। जब नगर निगम अतिक्रमण हटाने निकलता है तो उसका निशाना आमतौर पर वह गरीब रेहड़ी वाला या छोटा दुकानदार होता है जो किसी नेता की शरण में नहीं है, जिसके पास रिश्वत देने के पैसे नहीं हैं। जो बड़े व्यापारी हैं, जिन्हें धन्ना सेठ कहा जाता है, वे राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, अधिकारियों की मुट्ठी गरम करते हैं और शांति से अपना अतिक्रमण बनाए रखते हैं। यही कारण है कि शहर के बड़े बाजारों में, जहाँ सबसे ज़्यादा अतिक्रमण है, वहाँ कार्रवाई कभी नहीं होती।

शहर से गायब हो गए फुटपाथ की तरह ही पेड़ों की कहानी है, जो और भी दर्दनाक है। जब सड़कें चौड़ी करने का काम शुरू हुआ तो सबसे पहले पेड़ों पर आरी चली। विकास के नाम पर हजारों पुराने और घने पेड़ काट दिए गए। जो पेड़ दशकों से छाया दे रहे थे, जो पक्षियों के घर थे, जो शहर की हवा को साफ रखते थे, वे सब एक झटके में जमीन पर आ गए। सड़क चौड़ी हो गई, गाड़ियाँ ज्यादा दौड़ने लगीं, लेकिन पैदल चलने वाले के लिए न छाया बची, न फुटपाथ बचा। नए पेड़ लगाने की बात जरूर होती है, सरकारी कागजों में लाखों पेड़ लगाने के दावे भी होते हैं, लेकिन जमीन पर उनका नामोनिशान नहीं मिलता।

सरकारें आईं और गईं, योजनाएँ बनती रहीं और फुटपाथ के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये बहाए जाते रहे। कभी फुटपाथ को नए पत्थरों से ढका गया, कभी उस पर रंग-बिरंगी टाइलें लगाई गईं, कभी उसके किनारे लोहे की जालियाँ और लैंप पोस्ट खड़े किए गए। लेकिन इन सब कामों के बाद फुटपाथ पर पैदल यात्री के लिए जगह नहीं बनी। जो टाइलें लगाई गईं वे कुछ महीनों में उखड़ गईं, जो रोशनी के खंभे लगाए गए वे अँधेरे में डूब गए और जो फुटपाथ बने वे फिर से दुकानों और ठेलों से भर गए। पूरी कवायद केवल कागजी खानापूरी बनकर रह गई। शहरों की योजना बनाने वाले विभाग, जो जगह पैदल चलने वालों के लिए छोड़ते थे, उन्होंने भी धीरे-धीरे अपनी प्राथमिकता बदल ली। अब नई सड़कें बनती हैं तो उनमें गाड़ियों के लिए कई-कई लेन होती हैं लेकिन फुटपाथ या तो होता ही नहीं या इतना संकरा होता है कि दो लोग एक साथ नहीं चल सकते। यह मानसिकता बताती है कि हमारे नगर नियोजकों की नजर में पैदल चलने वाला नागरिक दोयम दर्जे का है। उधर, अदालतें अक्सर पैदल यात्रियों के पक्ष में फैसला देती रहती हैं, परंतु यह लालफीताशाही की भेंट चढ़ जाते हैं।

लब्बोलुआब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला कि फुटपाथ पर चलना पैदल यात्रियों का मौलिक अधिकार है, भले ही नगर निगम से लेकर राज्य सरकार तक हर स्तर पर जवाबदेही तय करता हो, जिस अधिकारी की देखरेख में फुटपाथ पर अतिक्रमण हो, उसे ज़िम्मेदार मानता हो, जो व्यापारी सड़क को अपना गोदाम समझे, उस पर सख्त कार्रवाई हो, की बात करता हो, लेकिन हकीकत यही है कि अब काफी देर हो चुकी है। सबसे बड़ी बाधा तो यही है कि जो सरकार सड़क से अतिक्रमण हटाने और फुटपाथ खाली कराने की बात सोचती है, उसको विरोध स्वरूप लामबंद वोटर लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने से गुरेज नहीं करते हैं। यही देश की नियति है, जिसे आसानी से नहीं बदला जा सकता है।

महतारी वंदन योजना : महिला सशक्तिकरण की नई इबारत, आत्मनिर्भरता और सम्मान का सशक्त आधार

डॉ. दानेश्वरी सम्भाकर, (उप संचालक), विवेक सरकार, (उप संचालक)रायपुर

किसी भी समाज और राज्य के विकास की वास्तविक तस्वीर तब उभरती है, जब उसकी महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सशक्त हों। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना इसी सोच को साकार कर रही है। यह योजना प्रदेश की लाखों महिलाओं के जीवन में आर्थिक संबल, आत्मविश्वास और सम्मान का नया अध्याय जोड़ रही है।

प्रदेश की पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। योजना के माध्यम से अब तक 28 किस्तों में कुल 18,165.19 करोड़ रुपये लाभार्थी महिलाओं के खातों में पहुंचाए जा चुके हैं। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव बन रही है।

आर्थिक सहायता से बढ़ा आत्मविश्वास

नारायणपुर जिले के ग्राम गोहाड़ा की श्रीमती गंडाय वडडे के लिए यह योजना जीवन में खुशहाली लेकर आई है। सीमित आय वाले परिवार में बच्चों की पढ़ाई, राशन और दैनिक जरूरतों को पूरा करना उनके लिए कठिन था। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। अब वे घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ परिवार के आर्थिक निर्णयों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे उनके आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

दूरस्थ अंचलों तक पहुंचा सशक्तिकरण

सुकमा जिले के ग्राम पंचायत बंडा के आश्रित गांव उसकेवाया की श्रीमती हूंगी माड़वी के जीवन में भी इस योजना ने सकारात्मक परिवर्तन लाया है। मजदूरी कर परिवार चलाने वाली हूंगी के लिए हर महीने मिलने वाली सहायता राशि कठिन समय में बड़ी राहत बन गई है। अब वे बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन, राशन और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर पा रही हैं। दूरस्थ और पहुंचविहीन क्षेत्र में रहने वाली श्रीमती हूंगी के लिए यह योजना आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत साबित हुई है।

स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर

महतारी वंदन योजना महिलाओं को केवल सहायता राशि प्रदान नहीं कर रही, बल्कि उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का माध्यम भी बन रही है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही विकासखंड के ग्राम मझगंवा की श्रीमती हेमा सिंह ने योजना से प्राप्त राशि को बचत और निवेश में लगाया। उन्होंने एक छोटा किराना स्टोर शुरू किया, जो आज परिवार की आय का स्थायी स्रोत बन चुका है।

सरगुजा जिला के ग्राम रामनगर की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की श्रीमती करियो ने योजना की राशि से बकरी पालन शुरू किया। आज यह गतिविधि उनके परिवार की आजीविका का मजबूत आधार बन गई है और उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है।

वहीं मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के ग्राम झाफल की श्रीमती गौरी राजपूत इस राशि का उपयोग अपनी शिक्षा के लिए कर रही हैं। उनके लिए यह योजना सपनों को साकार करने का माध्यम बन गई है।

निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक सम्मान में वृद्धि

योजना का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव महिलाओं के आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि के रूप में सामने आया है। महिलाएं अब इस राशि का उपयोग शिक्षा, स्वरोजगार, पशुपालन, बचत और पारिवारिक जरूरतों की पूर्ति में कर रही हैं। इससे न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और सम्मान भी बढ़ा है।

महिला सशक्तिकरण की मजबूत नींव

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महिला सशक्तिकरण को राज्य के समग्र विकास का आधार माना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे इसका लाभ प्रदेश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। आज महतारी वंदन योजना केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान प्रदान करने वाला व्यापक सामाजिक परिवर्तन अभियान बन चुकी है। गंडाय वडडे, हूंगी माड़वी, हेमा सिंह, करियो और गौरी राजपूत जैसी हजारों महिलाओं की प्रेरक कहानियां इस बात का प्रमाण हैं कि जब सरकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तब वे समाज में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन की आधारशिला बनती हैं।

निस्संदेह, महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के जीवन में नई आशा, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की धारा प्रवाहित कर रही है तथा प्रदेश के समावेशी और संतुलित विकास की मजबूत आधारशिला सिद्ध हो रही है।

नीली क्रांति से समृद्धि की ओर : मछली पालन बना ग्रामीण विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का आधार

एल.डी.मानिकपुरी, डॉ. ओम प्रकाश डहरिया, (सहायक जनसंपर्क अधिकारी)रायपुर

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि के साथ-साथ सहायक व्यवसायों को भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन्हीं में से एक है मछली पालन, जो आज केवल भोजन का स्रोत नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार, आय और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बन चुका है। कम लागत, कम समय में बेहतर उत्पादन और बाजार में लगातार बढ़ती मांग के कारण मछली पालन ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी किसानों से खेती को केवल धान उत्पादन तक सीमित न रखते हुए दलहन, तिलहन, उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन जैसे आयवर्धक व्यवसायों को अपनाने का आह्वान किया है। इसी सोच के अनुरूप भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन कर रही हैं, जिससे किसानों और ग्रामीण युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे सीमित भूमि और अपेक्षाकृत कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है। तालाब, जलाशय, नहर और अन्य जल स्रोतों का उपयोग कर किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। बढ़ती आबादी और पौष्टिक भोजन की मांग के कारण मछली की खपत लगातार बढ़ रही है। प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर मछली स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी मानी जाती है।

मत्स्य पालन न केवल किसानों की आय बढ़ाता है, बल्कि मत्स्य बीज उत्पादन, आहार निर्माण, परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीकों के प्रसार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें तालाब प्रबंधन, मत्स्य बीज उत्पादन, रोग नियंत्रण और विपणन संबंधी जानकारी दी जाती है। तकनीकी उन्नयन हेतु विशेष प्रशिक्षण भी संचालित किए जाते हैं। प्रगतिशील मत्स्य पालकों को राज्य के बाहर सफल मत्स्य पालन मॉडल देखने और नई तकनीकों को समझने के लिए अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाता है, जिससे वे अपने क्षेत्र में बेहतर तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं।

मत्स्य सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उत्पादन और विपणन व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को नाव और जाल उपलब्ध कराकर पारंपरिक मछली पकड़ने की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइस बॉक्स, तराजू और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता से छोटे मछुआरों को बेहतर बाजार और अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को स्पॉन संवर्धन और झींगा सह मछली पालन के लिए विशेष सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, रोजगार सृजन और मछुआरों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से संचालित इस योजना के तहत अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मत्स्य बीज उत्पादन बढ़ाने तथा नए तालाबों के निर्माण के लिए आकर्षक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे मत्स्य पालन के लिए आधारभूत संरचना मजबूत हो रही है। मछलियों की बेहतर वृद्धि के लिए संतुलित आहार व्यवस्था, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (फ्रअर) जैसी आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सजावटी मछली पालन इकाइयों तथा जलाशयों में केज कल्चर को बढ़ावा देकर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। शीत संयंत्र, प्रशीतित वाहन, आइस बॉक्स युक्त मोटरसाइकिल, ई-रिक्शा और लाइव फिश सेंटर जैसी सुविधाओं से मछलियों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए बेहतर विपणन सुनिश्चित किया जा रहा है। मत्स्यजीवियों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ भी संचालित की जा रही हैं। बंद अवधि के दौरान मछुआरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए बचत सह राहत योजना संचालित है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का भी योगदान रहता है। दुर्घटना, मृत्यु या अपंगता की स्थिति में मछुआरों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समूह बीमा योजना लागू है, जिससे संकट की घड़ी में उन्हें वित्तीय सहायता मिल सके।

मछली पालन आज ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। सरकार की विभिन्न योजनाएँ किसानों, युवाओं, महिलाओं तथा अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही हैं। आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएँ सृजित हो रही हैं। यदि किसान और इच्छुक हितग्राही इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो वे अपने नजदीकी मत्स्य विभाग कार्यालय से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मछली पालन न केवल आय बढ़ाने का साधन है, बल्कि आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

गुरु तेग बहादुर विरासत धाम के लिए छत्तीसगढ़ सिख समाज ने दिखाई एकजुटता

सुपेला गुरुद्वारा में हुई बैठक, पारसीवनी में बनेगा 350 फीट ऊंचा निशान साहिब

नई दृष्टिबिंदु /भिलाई

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी शताब्दी वर्ष के मौके पर शहीद बाबा दीपसिंह गुरुद्वारा भिलाई सुपेला में सोमवार को विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के पारसीवनी, रामटेक क्षेत्र में प्रस्तावित श्री गुरु तेग बहादुर गुरु विरासत धाम परियोजना और विश्व के सबसे ऊंचे 350 फीट निशान साहिब के निर्माण को लेकर चर्चा हुई।

गुरुद्वारों के प्रतिनिधि हुए शामिल

बैठक का नेतृत्व नागपुर से यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के गुरमीत सिंह खोकर ने किया। इसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न गुरुद्वारों के प्रधान, प्रबंधक, कमेटी सदस्य, सेवादार और सिख समाज के लोग शामिल हुए। बैठक में संयुक्त सचिव बाबुल डे, संकल्पना मनीष पाटिल, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिंग परिहार, सचिव नालंद रामटेके, कार्यकारिणी सदस्य रविकांत वर्मा, रामकुमार, अजय मेश्राम, रामकुमार गुजर, कमल गुप्ता मौजूद रहे।

ऐतिहासिक प्रयास बताया

बैठक में मौजूद गुरुद्वारा प्रबंधकों और सिख समाज के प्रतिनिधियों ने परियोजना को गुरु साहिब की महान विरासत से जुड़ा ऐतिहासिक प्रयास बताया। छत्तीसगढ़ के गुरुद्वारों के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी और इतिहास के रूप में जानी जाएगी। देश विदेश के सिख समाज से जुड़ने की अपील बैठक में संदेश दिया गया कि जब छत्तीसगढ़ का सिख समाज महाराष्ट्र में बनने वाले इस ऐतिहासिक प्रकल्प के लिए एकजुट होकर समर्थन कर रहा है, तब महाराष्ट्र सहित देश विदेश के सिख समाज को भी इस मिशन में बढ़ चढ़कर सहभागिता करनी चाहिए। बैठक में भिलाई सुपेला के विभिन्न गुरुद्वारों के प्रधान, सेवादार और सदस्य कुलदीप सिंह, हरपाल सिंह, बलविंदर सिंह, कुलवंत सिंह, तेजिंदर सिंह, गुरमीत सिंह, पलवंदर सिंह, भूपेंदर सिंह, गुरमेल सिंह, प्रजोत सिंह आदि उपस्थित थे।

प्रमुख संदेश

बैठक में कहा गया कि 350वां शहीद वर्ष केवल स्मरण का अवसर नहीं है बल्कि गुरु साहिब की विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प है।

श्री गुरु तेग बहादुर गुरु विरासत धाम केवल महाराष्ट्र का नहीं बल्कि पूरे देश विदेश के सिख समाज का प्रकल्प है। जब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की संगत एकजुट होगी तब गुरु विरासत का सपना जरूर साकार होगा।

खास खबर

नौगई तिहरे हत्याकांड में तीन और आरोपी गिरफ्तार, संख्या पहुंची 12

नई दृष्टिबिंदु /कोरिया

नौगई तिहरे हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 12 हो गई है। पुलिस ने जितेंद्र त्रिपाठी, अनिल तिवारी और मनीष त्रिपाठी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। गिरफ्तारी के बाद तीनों का मेडिकल परीक्षण जिला अस्पताल में कराया गया। एसपी रवि कुमार कुर्रे ने बताया कि मामले की गहराई से जांच जारी है। साजिश में शामिल हर आरोपी तक पुलिस पहुंचेगी। नए नाम सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। नौगई तिहरे हत्याकांड में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पहले भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि हर आरोपी की गिरफ्तारी तक जांच जारी रहेगी।

सोशल मीडिया पर नाबालिग की तस्वीर वायरल करने वाले को 3 साल की सजा

नई दृष्टिबिंदु /रायपुर

नाबालिग की फोटो और मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर डालकर लैंगिक उत्पीड़न करने के मामले में रायपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को महिला पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 1 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। थाना पुरानी बस्ती में प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 151/2025 दर्ज किया गया था। आरोपी रूपेश यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी कुशालपुर, पुरानी बस्ती, रायपुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79, आईटी एक्ट की धारा 67 और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 व 15 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। जांच में साबित हुआ कि आरोपी ने पीड़िता की फोटो और मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर अश्लील और लैंगिक उत्पीड़न से जुड़ी सामग्री प्रकाशित की थी। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय पॉक्सो, रायपुर ने 17 जून 2026 को आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

भिलाई में वॉशिंग पाउडर की आड़ में चल रही थी अवैध गुटखा फैक्ट्री, पुलिस ने मारा छापा

भिलाई। दुर्ग पुलिस ने मंगलवार रात कचांदूर स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गोदाम में वॉशिंग पाउडर पैकिंग के नाम पर जर्दा युक्त गुटखा तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में तैयार गुटखा, कच्चा माल और मिक्सिंग मशीन जब्त की है। आरोपी गोदाम किराए पर लेने वाला मोहम्मद सानू फरार है। मामला जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार कचांदूर का यह गोदाम सुपेला निवासी मोहम्मद मुस्तफा का है। करीब 20 दिन पहले उत्तर प्रदेश उन्नाव निवासी मोहम्मद सानू ने डिटर्जेंट पाउडर निर्माण और पैकेजिंग के नाम पर गोदाम किराए पर लिया था। इसके बाद से उसका गोदाम मालिक से संपर्क टूट गया और मोबाइल भी बंद आने लगा। इस बीच परिसर में तैनात गार्ड ने अंदर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दी। शक होने पर गोदाम मालिक मोहम्मद मुस्तफा ने जेवरा सिरसा चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सूचना पर पुलिस ने मंगलवार रात गोदाम में दबिश दी। जांच के दौरान 32 बड़े बोरों में तैयार गुटखा, 32 बोरों में मीठी सुपारी, गुटखा बनाने का रॉ मटेरियल और मिक्सिंग मशीन बरामद हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए फूड सेफ्टी विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। बरामद सामग्री फूड सेफ्टी अधिकारियों को सौंप दी गई है। पुलिस की रेड के दौरान गोदाम किराए पर लेने वाला मोहम्मद सानू मौके पर नहीं मिला। आशंका है कि उसे छापे की भनक लग गई थी। जेवरा पुलिस के अनुसार गोदाम मालिक की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। जांच में गुटखा निर्माण से जुड़ा कच्चा माल और पैकिंग सामग्री मिली है। मामले में आगे की कार्रवाई फूड सेफ्टी विभाग कर रहा है। फरार आरोपी की तलाश जारी है।

बीएसपी स्क्रैप चोरी मामले में कारोबारियों और हिस्ट्रीशीटरों तक पहुंची जांच टीम

सिंडिकेट पर कसा शिकंजा, संदेही तलाश रहे राजनीतिक संरक्षण

नई दृष्टिबिंदु /भिलाई

भिलाई इस्पात संयंत्र से 250 टन लौह स्क्रैप चोरी के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। कार्रवाई की आंच सिंडिकेट से जुड़े कारोबारियों और हिस्ट्रीशीटरों तक पहुंच गई है। पुलिस की पूछताछ में कई नाम सामने आने के बाद संदेहियों में बेचैनी बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई के डर से आधा दर्जन से अधिक संदेही राजनीतिक संरक्षण तलाश रहे हैं।

3.22 करोड़ का स्क्रैप जब्त

भिलाई तीन थाना पुलिस ने 26 मई को ग्राम अकलोरीडीह में छापेमारी कर बीएसपी से चोरी किया करीब 250 टन लौह स्क्रैप, फ्लू डस्ट, भारी वाहन, बैकहोलोडर और अन्य मशीनरी जब्त की थी। जब्त सामग्री की कीमत लगभग 3.22 करोड़ रुपए आंकी गई। मामले में पहले स्थानीय स्तर पर कार्रवाई हुई। इसके बाद सिंडिकेट के कथित सरगना संजय सिंह को नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया। स्क्रैप की नापतौल और बिक्री की तैयारी में शामिल आकाश सिंह को भी पुलिस ने पकड़ा।

फरार आरोपियों की तलाश

मामले में हिमांशु खंडेलवाल, गिरीश खंडेलवाल, जान सलीम और 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी अभय सिंह समेत अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों और बयानों के आधार पर पूरे सिंडिकेट तक पहुंचकर कार्रवाई की जाएगी।

प्लांट के भीतर चल रहा था कार्यालय

जांच में सामने आया कि स्क्रैप चोरों का नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। फ्लू डस्ट परिवहन के नाम पर बीएसपी प्लांट के भीतर ही एक कार्यालय संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने यहां से वीडियो और फोटोग्राफी कर साक्ष्य जुटाए हैं। सूत्रों के अनुसार इस कार्यालय के संचालन में कुछ हिस्ट्रीशीटरों की भूमिका की भी जांच हो रही है।

सीएसपी बोले, जांच जारी है

सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना आगे बढ़ाई जा रही है। सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। जल्द ही आगे की कार्रवाई होगी।

आईजी बालाजी राव ने 40 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों की ली बैठक

नई दृष्टिबिंदु /राजनांदगांव

पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज बालाजी राव ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मीटिंग हॉल में चार जिलों के 40 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों की परिचयात्मक बैठक ली। इसमें प्रशिक्षण कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।

चार जिलों के प्रशिक्षु शामिल

बैठक में राजनांदगांव के 13, कबीरधाम के 12, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के 6 और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के 9 प्रशिक्षु उप निरीक्षक मौजूद रहे। आईजी ने सभी को निष्ठा, ईमानदारी और लगन से पुलिस का प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा करने के लिए प्रेरित किया।

इन कार्यों का करना होगा प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीट आरक्षक, संत्री ड्यूटी, मुल्जिम पेशी, प्रधान आरक्षक गश्त, प्रधान आरक्षक मोहर्रिर, प्रधान आरक्षक मालखाना, लोक अभियोजन से संबद्धता, जिला विशेष शाखा, एमएलसी, एफएसएल कार्य, न्यायालयीन कार्य, जेल संबंधी कार्य और थाना प्रभारी का स्वतंत्र प्रभार शामिल है। आईजी ने सभी कार्य निर्धारित समय में पूरे कर रजिस्टर में हस्तलिपि से प्रविष्टि करने के निर्देश दिए।

डिजिटल सिस्टम सीखने पर जोर

अपने उद्बोधन में आईजी बालाजी राव ने कहा कि बेसिक पुलिसिंग के साथ नवीन और डिजिटल कार्यों को सीखना जरूरी है। नेटग्रिड, क्राइमेक, मेडलीपार, सीसीटीएनएस, ई-साक्ष्य, ई-मालखाना, ई-रोजनामचा, ई-चाजर्शीट, आईसीजेएस जैसे सिस्टम का व्यावहारिक उपयोग सीखें। खुद को डिजिटली लिटरेट बनाएं। भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का व्यवहारिक अनुपालन करें। उन्होंने नक्सलवाद के बाद साइबर क्राइम की चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार रहने को कहा।

बैठक में पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, रक्षित निरीक्षक लोकेश कसेर, एएसपी कबीरधाम अमित पटेल, एएसपी मोहला-मानपुर-अं.चौकी पीतांबर पटेल और एएसपी खैरागढ़-छुईखदान-गंडई नितेश गौतम उपस्थित रहे।

3 जुलाई को रायपुर में होगा 'नारी संगम' का आयोजन

रायपुर। जेसीआई रायपुर वामा कैपिटल द्वारा महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम नारी संगम का आयोजन 3 जुलाई को दीनदयाल ऑडिटोरियम में किया जाएगा। यह रायपुर में तीसरी बार आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में वामा कैपिटल का 16वां फाउंडेशन डे भी मनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ट्रेनर देंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय प्राइम ट्रेनर और जेसीआई सीनेटर रजनीश अग्रवाल प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देंगे। उनका सत्र लव यू जिंदगी विषय पर होगा। इसमें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना, आत्मविश्वास विकसित करना और व्यक्तिगत विकास जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। आयोजन में पूरे छत्तीसगढ़ की करीब 300 संस्थाओं से महिलाओं की सहभागिता होगी। रायपुर से बाहर की संस्थाओं और उत्कृष्ट संस्थाओं का मंच पर सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 100 से अधिक सदस्यों की टीम विभिन्न समितियों के माध्यम से तैयारी में जुटी है। इस आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम की को-ऑर्डिनेटर जया अरोरा और अध्यक्ष धृति वैभव शर्मा ने बताया कि संस्थापक अध्यक्ष लीना वाढेर, संयोजक रुपाली दुबे और चैप्टर इंचार्ज आंचल पंजवानी के निर्देशन में विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। टीम के सदस्य पूरे समर्पण के साथ तैयारियों में जुटे हैं। आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को सीखने और एक साझा मंच पर जुड़ने का अवसर देना है।

पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन

भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भिलाई भाजपा कार्यालय व कोहका मंडल के तीन दर्शन मंदिर में उनके चित्र पर भाजपा नेता कन्हैया सोनी, विरेंद्र साहू आदि ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

सेक्टर-9 अस्पताल और मैत्री बाग को लेकर बीएसपी प्रबंधन पर उठाए सवाल

भिलाई की बसाहट बचाने हर स्तर पर लड़ेंगे जरूरत पड़ी तो बलिदान दूंगा : विधायक देवेंद्र

नई दृष्टिबिंदु /भिलाई

भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सेक्टर-9 अस्पताल, मैत्री बाग और भिलाई टाउनशिप की बसाहट को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भिलाई की पहचान और बसाहट को किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो वे बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

बीएसपी प्रबंधन पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप

मीडिया से चर्चा में विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि पूर्व में हुए जनआंदोलन के दौरान बीएसपी प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि सेक्टर-9 अस्पताल को न बेचा जाएगा और न ही निजी संस्था को लीज पर दिया जाएगा। मैत्री बाग और टाउनशिप की मूल बसाहट को भी सुरक्षित रखने की बात कही गई थी। लेकिन छह माह बीतने के बाद भी प्रबंधन ने इस पर कोई पहल नहीं की। लगातार बैठक की मांग के बावजूद बीएसपी चर्चा से बच रहा है।

नोटिस से लोगों में बढ़ी चिंता

विधायक ने कहा कि टाउनशिप क्षेत्र के निवासियों को नोटिस दिए जाने से चिंता बढ़ गई है। लोगों को डर है कि वर्षों पुरानी बसाहट को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। लीजधारकों की रजिस्ट्री रोकने और लगातार नोटिस जारी होने से असुरक्षा का माहौल बन रहा है। चर्चा है कि सेक्टर क्षेत्र के बड़े हिस्से को खाली कराकर निजी हाथों में सौंपने की योजना है।

भिलाई देश की साझा संस्कृति का प्रतीक

देवेंद्र यादव ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एकता और औद्योगिक विकास की सोच के साथ भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की थी। भिलाई देश के विभिन्न राज्यों से आए लोगों की साझा संस्कृति और भाईचारे का प्रतीक है। ऐसे शहर की पहचान को समाप्त करने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा।

गांधीवादी तरीके से चलेगा आंदोलन

विधायक ने कहा कि यह लड़ाई पूरे भिलाई की है। हर नागरिक, कमर्चारी और श्रमिक के भविष्य से यह मुद्दा जुड़ा है। उन्होंने घोषणा की कि जनसंघर्ष की शुरुआत कर दी गई है। आने वाले दिनों में वे नोटिस पाने वाले परिवारों से संवाद कर जनसमर्थन जुटाएंगे। यह आंदोलन गांधीवादी और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भिलाई की बसाहट हमारी पहचान है। इसे बचाने के लिए यदि सर्वस्व अर्पित करना पड़े तो भी पीछे नहीं हटेंगे। भिलाईवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग

-:: ईश्तहार ::-

(रा०प्र०क० /202606101000148/अ-6.अ/वर्ष 2025-26)

इस न्यायालय का रा.प्र. कं. 202606101000148/अ-6 (अ) वर्ष 2025-26 आवेदिका/आवेदक महेन्द्र कुमार यादव पिता स्व. राजदेव यादव निवासी शांति नगर कोहका मिलाई तह. व जिला दुर्ग ग्राम कोहका प.ह.नं. 46, रा. नि.मं. कोहका, तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि पुराना खसरा नं. 435/2 का दु. नया खसरा नं. 6179 रकबा 0.020 हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती सुधा अग्रवाल ध.प. प्राणकिशन अग्रवाल से रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से क्रेता/आवेदक के पिता राजदेव यादव पिता भुनेश्वर यादव द्वारा क्रय किया गया था। नामांतरण पश्चात ऋण पुस्तिका में आवेदक का नाम दर्ज है। किन्तु वतर्मान ऑनलाईन अभिलेख में सजी एम पिता के. मतई का नाम दर्ज हो गया है। जिसे सुधार किये जाने हेतु एवं वर्तमान में क्रेता/आवेदक के पिता राजदेव पिता स्व. भुनेश्वर यादव की मृत्यु दिनांक 09.11.2026 को हो जाने के कारण मृतक का नाम विलोपित कर उसके वैध वारिसानो का नाम दर्ज करने करते हुऐ त्रुटि सुधार किये जाने बाबत आवेदनमय दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त संबंध में आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 08/07/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 17/06/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग

-:: ईश्तहार ::-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय का रा.प्र.क्रं......./अ-6/ वर्ष 2025-26 में आवेदिका/ आवेदक मोहम्मद मोदरिसर अंसारी आ./ध.प. श्री. मो. अलीमुद्दीन अंसारी निवासी सुपेला भिलाई तह. दुर्ग व जिला दुर्ग द्वारा ग्राम कोहका प. ह. नं. 45 रा.नि.मं. कोहका व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं. 1626/2 रकबा 0.020 हे. है। जो भूमिस्वामी असमत आरा ध.प. मो. अलीमउद्दीन के नाम पर दर्ज है। जिसमें भूमिस्वामी असमत आरा ध.प. मो. अलीमउद्दीन की मृत्यु दिनांक 23/6/2023 को फौत हो जाने के कारण मृतक का नाम खाते से विलोपित कर उसके वैध वारिसानों का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्त भूमि फौती नामांतरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 13/7/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 19/6/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग

-:: ईश्तहार ::-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय का रा.प्र.क्रं......./अ-6/ वर्ष 2025-26 में आवेदिका/ आवेदक मोहम्मद मोदरिसर अंसारी आ./ध.प. श्री. मो. अलीमुद्दीन अंसारी निवासी सुपेला भिलाई तह. दुर्ग व जिला दुर्ग द्वारा ग्राम कोहका प. ह. नं. 45 रा.नि.मं. कोहका व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं. 3300/5 रकबा 0.014 हे. है। जो भूमिस्वामी मोहम्मद अलीमुउद्दीन आ. स्व. मोहम्मद शरीफउद्दीन के नाम पर दर्ज है। जिसमें भूमिस्वामी मोहम्मद अलीमुउद्दीन आ. स्व. मोहम्मद शरीफउद्दीन की मृत्यु दिनांक 23/6/2023 को फौत हो जाने के कारण मृतक का नाम खाते से विलोपित कर उसके वैध वारिसानों का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्त भूमि फौती नामांतरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 13/7/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 19/6/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

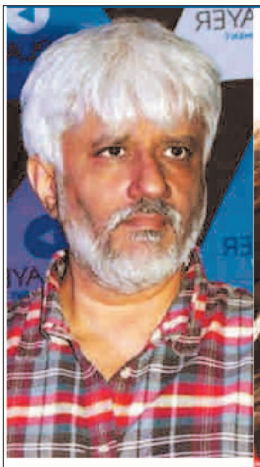

'हॉन्टेड 3डी' के बाद फिर डराएंगे विक्रम भट्ट

इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर विक्रम भट्ट निर्देशित फिल्म 'हॉन्टेड 3डी' खूब नोट छाप रही है। इस फिल्म की सफलता को देखते हुए निर्देशक विक्रम भट्ट अब प्रोड्यूसर आनंद पंडित के मिलकर अगली फिल्म '1920 कोल्ड विंटर' बनाएंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा भी की जा चुकी है।

'1920' फ्रैंचाइजी का नया चैप्टर होगा शुरू

फिल्म 'हॉन्टेड 3डी' के बाद आनंद पंडित और विक्रम भट्ट अपकमिंग फिल्म '1920: कोल्ड विंटर' के लिए फिर साथ आए हैं। 'हॉन्टेड 3डी इकोस ऑफ द पास्ट' की सफलता के बाद, प्रोड्यूसर आनंद पंडित और फिल्ममेकर विक्रम भट्ट ने अगली हॉरर फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। यह नई फिल्म हॉरर जॉनर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। '1920' फ्रैंचाइजी का नया चैप्टर इसके जरिए फिर से शुरू होगा।

फिल्म को लेकर अधिक जानकारी मेकर्स द्वारा कुछ दिनों बाद साझा की जाएगी। सैकनिल्क के मुताबिक 'हॉन्टेड 3डी-इकोज ऑफ द पास्ट' ने 8वें दिन यानी शुक्रवार को 51 लाख रुपये कमाए हैं। जबकि 7वें दिन 1.15 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म का कुल कलेक्शन भी अब तक 16.41 करोड़ रुपये हो चुका है। वीकएंड पर भी यह फिल्म अच्छा कलेक्शन कर सकती है। इस फिल्म में वीएफएक्स और एआई का खूब इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिए सीन्स को भयावह बनाया गया है। साथ ही इसमें एक लव स्टोरी को भी दिखाया गया है। इसकी कहानी में एक आदमी दूर-दराज के इलाके में बनी हवेली में आकर रहने लगता है। लेकिन यहां पर उसके साथ भयावह घटनाएं घटने लगती हैं। मामला भूत-प्रेत और उसके अतीत से जाकर जुड़ जाता है। इस फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती, चेतना पांडे, मनवीर चौधरी और श्रुति प्रकाश जैसे एक्टर्स नजर आए हैं।

जल्द एंजेलिना जोली के साथ काम करेंगी प्रियंका चोपड़ा?

करियर में आए बदलावों पर तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड से निकल हॉलीवुड तक नाम कमा चुकीं प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल स्टार हैं। इन दिनों वे अपनी आगामी फिल्म 'वाराणसी' को लेकर सुर्खियों में हैं। यह भारी-भरकम बजट में बनी फिल्म है, जिससे प्रियंका चोपड़ा को बहुत उम्मीदे हैं। एसएस राजामौली की इस फिल्म में प्रियंका के अलावा महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। हाल ही में प्रियंका ने इस फिल्म पर बात की। साथ ही बताया कि वे जल्द ही एंजेलिना जोली के साथ काम करेंगी।

एंजेलिना जोली से मिलती है प्रेरणा

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपने फ्यूचर प्लान पर 'फॉर्च्यून इंडिया' से बात करते हुए बताया कि वे एंजेलिना जोली के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह प्रोजेक्ट कोई फिल्म होगी, विज्ञापन होगा या कोई वैरिटी से जुड़ा काम। प्रियंका ने हॉलीवुड की उन महिलाओं में एंजेलिना जोली का भी जिक्र किया, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती है।

'वाराणसी' पर जताई खुशी

प्रियंका चोपड़ा फिलहाल एसएस. राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' के आखिरी कुछ शेड्यूल की शूटिंग कर रही हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने करियर का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया है। उन्होंने कहा, 'हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वह बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी है। ऐसा काम बहुत समय से देखने को नहीं मिला है। मैं

न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया के लिए इसे लेकर बहुत उत्साहित और सम्मानित महसूस कर रही हूं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी ग्लोबल रिलीज होगी और लोगों को पता चलेगा कि हम पिछले तीन वर्षों से किस चीज पर काम कर रहे हैं।'

खुद चुन सकती हूं प्रोजेक्ट

प्रियंका चोपड़ा ने अपने करियर में हुई तरक्की के बारे में बात की। हैदराबाद में शूटिंग के दौरान अपनी जिंदगी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, 'फिल्म 'वाराणसी' के सेट पर शूटिंग का माहौल बहुत मजेदार है। सभी एक्टर्स के परिवार साथ में हैं। हम मस्ती कर रहे हैं। हंस-बोल रहे हैं। साथ ही काम पर पूरा ध्यान है। रिहर्सल और फोकस के साथ काम हो रहा है'। इतने वर्षों में अपने करियर में हुई तरक्की पर बात करते हुए देसी गर्ल ने माना कि अब उन्हें काम में ज्यादा क्रिएटिव आजादी मिलती है। उन्होंने कहा, 'जब मैंने शुरुआत की थी, तब स्क्रिप्ट्स मेरे हिसाब से नहीं लिखी जाती थीं। अब मैं अपने प्रोजेक्ट्स खुद चुन सकती हूं और बना सकती हूं। इंटरनेशनल लेवल पर प्रियंका चोपड़ा फिल्ममेकर मीरा नायर की बायोपिक ड्रामा 'अमरी' से भी जुड़ी हुई हैं।

रणवीर सिंह का प्रण, 18 महीने तक नहीं देंगे कोई इंटरव्यू; 'डॉन 3' विवाद पर साधी चुप्पी

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों 'डॉन 3' को लेकर चल रहे विवाद के कारण सुर्खियों में हैं। खबरों के मुताबिक, रणवीर ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने तय किया है कि वह अगले 18 महीनों तक किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं देंगे और इस विवाद पर कोई बयान भी नहीं देंगे। मीडिया से बनाए रखेंगे दूरी रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर ने यह बात एक ट्रेड जर्नलिस्ट से मुलाकात के दौरान खुद कही। उन्होंने साफ कर दिया कि वह 'डॉन 3' से जुड़े किसी भी सवाल पर बात नहीं करेंगे और अपनी अगली फिल्म 'प्रलय' की रिलीज तक मीडिया से दूरी बनाए रखेंगे।

दरअसल, रणवीर सिंह और फिल्ममेकर फरहान अख्तर के बीच 'डॉन 3' को लेकर मतभेद हो गए थे। कहा जा रहा है कि रणवीर फिल्म की स्क्रिप्ट और बार-बार हो रही देरी से खुश नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला लिया। जो मामला पहले सिर्फ कास्टिंग बदलने का लग रहा था, वह अब कानूनी विवाद में बदल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर से 45 करोड़ रुपये की मांग की है। वहीं, FWICE ने भी कुछ समय के लिए रणवीर के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन का आदेश जारी किया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है।

क्या है प्रलय की कहानी

अब बात करते हैं रणवीर की अगली फिल्म 'प्रलय' की। यह एक पोस्ट-अपोकैलिप्टिक जॉम्बी थ्रिलर फिल्म होगी, जिसकी कहानी तबाह हो चुके मुंबई पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं, जो मशहूर फिल्ममेकर हंसल मेहता के बेटे हैं। 'प्रलय' उनका थिएटर में डायरेक्शन डेब्यू भी होगा। जय मेहता इससे पहले 'स्कैम 1992' और 'लूटेरे' जैसे प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं। फिलहाल, 'प्रलय' की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन तब तक रणवीर सिंह पूरी तरह चुप्पी साधे रहेंगे और 'डॉन 3' विवाद पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे।

क्या बनने जा रही है 'स्त्री 3' अभिषेक बनर्जी ने किया खुलासा

'स्त्री' और 'स्त्री 2' की सफलता के बाद अब ऑडियंस को इस हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइजी के अगले भाग का इंतजार है। 'स्त्री' में जना का किरदार निभाने वाले अभिषेक बनर्जी भी फ्रेंचाइजी के अगले भाग का इंतजार कर रहे हैं। अमर उजाला से खास बातचीत में अभिषेक ने कहा, 'यह फिल्म बननी भी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सिलसिला आगे चलता रहेगा।'

फ्रेंचाइजी को चाहिए नई और युवा एनर्जी

फ्रेंचाइजी की कास्टिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर अभिनेता ने कहा, 'जहां तक कास्ट की बात है, फिलहाल तो मेरी यही दुआ है कि अगले कुछ साल तक यही टीम (राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक) बनी रहे। लेकिन आखिरकार हर चीज का एक समय होता है। किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे आप किसी भी मुकाम पर हों, एक समय ऐसा आता है जब नई पीढ़ी को आगे आने के लिए जगह देनी पड़ती है।' उन्होंने आगे कहा, 'इस तरह की फिल्मों में एक खास तरह की यंग एनर्जी की जरूरत होती है। अगर हम 55 या 60 साल की उम्र में भी वही किरदार निभाते रहें तो ऑडियंस को उतना मजा नहीं आएगा इसलिए जब तक हम उस किरदार की ताजगी और एनर्जी को बनाए रख सकते हैं, तब तक जरूर इसका हिस्सा बने रहना चाहेंगे। हां, जिस दिन हमारे निर्माता या निर्देशक को लगेगा कि अब किसी नई एनर्जी की जरूरत है, तो वह फैसला भी हमें स्वीकार करना होगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।'

'उम्मीद है 2028 तक रिलीज हो जाएगी'

फ्रेंचाइजी के अगले भाग को लेकर अभिषेक ने कहा, 'इसका इंतजार मैं भी उतना ही कर रहा हूं जितना ऑडियंस कर रही है। उम्मीद है कि 2028 तक फैंस को 'स्त्री' की एक नई पेशकश देखने को मिल जाएगी। फिलहाल तो यही कहूंगा कि यह यूनिवर्स लगातार बड़ा और मजबूत होता जा रहा है, इसका अगला भाग 'शक्ति शालिनी' भी अभी बन रहा है।'

'बॉक्स ऑफिस हिट के बिना इंडस्ट्री गंभीरता से नहीं लेती'

बातचीत के दौरान अभिषेक ने यह भी माना कि यह फिल्म उनके करियर की सबसे अहम फिल्मों में से एक रही है। उनके मुताबिक, इसकी सफलता के बाद इंडस्ट्री में उन्हें देखने का नजरिया बदल गया। अभिनेता ने कहा, 'मुझे लगता है कि 'स्त्री' मेरे करियर की सबसे बड़ी गेम चेंजर रही। जब यह फिल्म आई और उसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की, तब चीजें बदलनी शुरू हुईं। मेरा मानना है कि हमारी इंडस्ट्री में जब तक आपकी फिल्में पैसा नहीं कमातीं, तब तक आपको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। टैलेंट अपनी जगह है, लेकिन आखिर में बॉक्स ऑफिस और बिजनेस भी बहुत मायने रखता है। हम सब यह बात जानते हैं।'

'अज्जी' को मिली सराहना, लेकिन पहचान बाद में मिली

उन्होंने आगे कहा, 'इससे पहले मेरी एक फिल्म थी 'अज्जी', इसे सराहना मिली थी लेकिन बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे। उस फिल्म के बाद मुझे बहुत ज्यादा काम नहीं मिला। लेकिन इसके बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। उसी फिल्म की वजह से मुझे आगे कई बड़े और दिलचस्प प्रोजेक्ट्स मिले। इसलिए मैं कहूंगा कि मेरे करियर में वह एक ऐसा पड़ाव था, जहां पहली बार लगा कि अब इस इंडस्ट्री में मुझे लगातार काम मिलता रहेगा। उसने मुझे एक पहचान दी और मेरे लिए कई नए रास्ते खोले।'

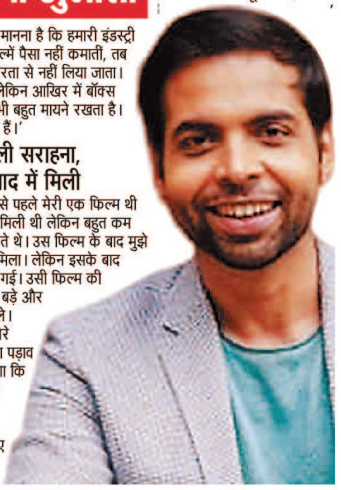

आजकल बुरी फिल्मों को भी अच्छा बताया जाता है

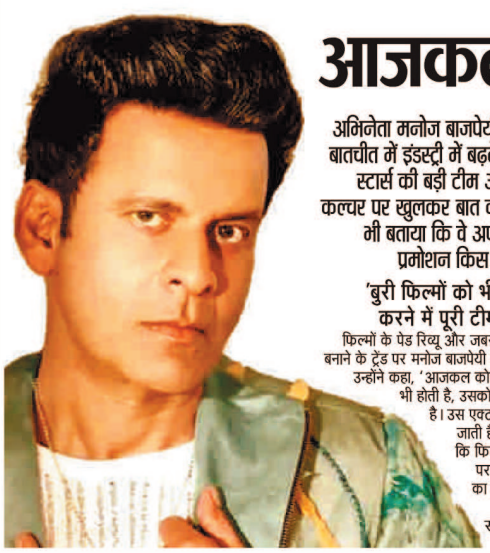

अभिनेता मनोज बाजपेयी ने हाल ही में बातचीत में इंडस्ट्री में बढ़ते पेड रिव्यू ट्रेंड, स्टार्स की बड़ी टीम और बदलते वर्क कल्चर पर खुलकर बात की। उन्होंने यह भी बताया कि वे अपनी फिल्मों का प्रमोशन किस तरह करते हैं?

'बुरी फिल्मों को भी अच्छा साबित करने में पूरी टीम लग जाती है'

फिल्मों के पेड रिव्यू और जबरदस्ती अच्छा माहौल बनाने के ट्रेंड पर मनोज बाजपेयी ने बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा, 'आजकल कोई भी फिल्म जो बुरी भी होती है, उसको अच्छा बताया जाता है। उस एक्टर की पूरी टीम लग जाती है ये साबित करने में कि फिल्म अच्छी है...उनका परफॉर्मेंस बहुत कमाल का है। तो जो चीज बुरी है, उसको अच्छा साबित करने के लिए पूरी टीम लगी रहती है जी। और ये सब मैंने भी पढ़ा है, देखा नहीं। मैं जिस तरह का काम करता हूं, उसमें ये सब तो होता नहीं है।'

मेरे फैसले मैं खुद लेता हूं

आज कई कलाकारों के फैसले उनकी टीम तय करती है। लेकिन मनोज कहते हैं कि उन्होंने हमेशा अपने फैसले खुद लिए हैं। उन्होंने कहा, 'मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मैं अपने फैसले खुद लेता हूं। स्क्रिप्ट पढ़ता हूं या फिर उसका नरेशन लेता हूं। ज्यादातर मैं स्क्रिप्ट पढ़ना पसंद करता हूं। आखिर में फैसला मेरा ही होता है।'

मेरे सेट पर मेरी टीम का कोई आदमी नहीं होता

मनोज बाजपेयी ने कहा कि काम के दौरान वह अपनी निजी टीम को सेट से दूर रखते हैं और इसे डिसिप्लिन का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने कहा, 'अगर आप मेरे सेट पर आकर देखें, तो आपको मेरी टीम का कोई आदमी आसपास दिखाई नहीं देगा। मीडिया इंटरैक्शन के दौरान भी आप देख रहे हैं- प्रोडक्शन के लोग हैं, कैमरा टीम है, लेकिन मेरी टीम का कोई सदस्य यहां मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है।' आगे उन्होंने कहा, 'जब हम काम कर रहे होते हैं, मेरा स्टाफ उस दायरे से बाहर रहता है। वहां कैमरा है, डायरेक्टर है, मेरे साथ दूसरे कलाकार हैं। वो एक अलग जोन होता है। उसमें मेरा बॉय, असिस्टेंट या मेकअप मैन तभी आएगा जब उसे बुलाया जाएगा। उनका काम कहीं और है, इस स्पेस में नहीं।'

मुझे बड़ी टीम के साथ चलने की जरूरत नहीं पड़ती

जहां कई कलाकार बड़े सपोर्ट सिस्टम के साथ चलते हैं, वहीं मनोज का कहना है कि उन्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। उन्होंने कहा, 'अब हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी है। मैं किसी को जज नहीं करता। जो बात आप कर रही हैं, उसके बारे में मैं कभी-कभी पढ़ लेता हूं, लेकिन वो दुनिया मेरे लिए काफी अनजान है। हो सकता है किसी अभिनेता को इतने सपोर्ट सिस्टम की जरूरत हो, मुझे नहीं है। मैं अपने लिए काफी हूं। मेरा कॉस्ट्यूम, मेरा मेकअप, बहुत सारी चीजें मैं खुद संभाल लेता हूं।'

कई बार हेयर स्टाइलिस्ट भी साथ नहीं ले जाता

मनोज का कहना है कि वह फिल्मों में दिखावे के बजाय जरूरत के हिसाब से चीजें तय करते हैं। उन्होंने कहा, 'कई बार मैं अपने हेयर स्टाइलिस्ट को भी साथ नहीं ले जाता। अगर फिल्म को उसकी जरूरत नहीं है, तो वो नहीं जाता। कई बार तो मेरे मेकअप मैन की तारीफ इस बात के लिए होती है कि उसने कुछ किया ही नहीं, बस मुझे वैसे ही रहने दिया। और कई फिल्मों में तो वो आता भी नहीं, सिर्फ तब आता है जब उसकी वाकई जरूरत हो।'

मैं सिर्फ अपनी फिल्मों का प्रमोशन करता हूं, बाकी चीजों में नहीं पड़ता

मनोज कहते हैं कि वह अपनी फिल्मों का प्रमोशन जरूर करते हैं, लेकिन चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने में यकीन नहीं रखते। उन्होंने कहा, 'हम अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी फिल्म को लेकर जागरूक हों। उसके बाद फिर हम अगली फिल्म में चले जाते हैं। और मैं इस बात पर यकीन करता हूं कि जो होगा, वो होगा। अपना काम शिद्दत से कीजिए, क्योंकि आपके भाग्य का कोई कुछ नहीं ले जा सकता।'

कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी आमजन की समस्याएं, 80 आवेदनों पर दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

प्रशासन की तत्परता के चलते कई नागरिकों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया, आवेदकों में संतोष और विश्वास का माहौल देखने को मिला

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

जिले के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज सोमवार को कलेक्टर प्रतिष्ठ ममगाई के द्वारा कलेक्टरेट स्थित कक्ष में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जनदर्शन में जिले के विभिन्न अंचलों से आए नागरिकों ने अपनी मांगों, समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। जनदर्शन के दौरान कलेक्टर प्रतिष्ठ ममगाई ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर बुलाकर एवं दूरभाष के माध्यम से चर्चा कर कई प्रकरणों का तत्काल निराकरण कराया। प्रशासन की तत्परता के चलते कई नागरिकों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जिससे आवेदकों में संतोष एवं विश्वास का माहौल देखने को मिला।

आज आयोजित जनदर्शन में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 80 आवेदन प्राप्त हुए। तात्कालिक महत्व के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करते हुए समाधान किया गया, जबकि गंभीर एवं जांच योग्य प्रकरणों को टीएल पंजी में दर्ज कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जनदर्शन में निराश्रित पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, बैटरी चालित ट्रायसायकल प्रदाय, कटा हुआ रकबा जोड़ने, खाद गड्ढा हटाने, आम रास्ता खुलवाने सहित अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ममगाई ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को नियमानुसार शीघ्र एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ निराकरण किया जाए, ताकि आम नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

15 अक्टूबर तक रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, भंडारित रेत से होगी आपूर्ति

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2016 एवं 2020 की गाइडलाइन के अनुरूप वर्षा ऋतु के दौरान नदियों में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी क्रम में बेमेतरा जिले में भी 10 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक सभी नदी क्षेत्रों में रेत खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मानसून अवधि में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण तथा नदी तंत्र को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध प्रभावी किया गया है। वर्षा ऋतु के दौरान नदी क्षेत्रों में खनन से पर्यावरणीय असंतुलन, नदी तटों के कटाव एवं अन्य प्राकृतिक समस्याओं की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा नदी से रेत का उत्खनन, परिवहन अथवा अवैध खनन किया जाना नियम विरुद्ध माना जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राजस्व, खनिज, पुलिस एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को सतत निगरानी एवं जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्माण कार्यों एवं आमजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत रेत भंडारण अनुज्ञा प्राप्त स्थलों के माध्यम से रेत की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि प्रतिबंध अवधि में भी आवश्यक निर्माण गतिविधियां प्रभावित न हों। संबंधित एजेंसियों एवं भंडारण अनुज्ञाधारकों को निर्धारित नियमों के अनुसार रेत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने आमजन, ठेकेदारों एवं खनन से जुड़े व्यक्तियों से अपील की है कि वे शासन के निर्देशों का पालन करें तथा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन से दूर रहें। पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है।

खास खबर

बिहान महिलाओं ने बनाई प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी एक अलग पहचान

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) एवं कृषि विभाग के सहयोग से ग्राम पेंड्रावन, जनपद पंचायत धमधा की महिलाओं ने जैविक खेती को अपनाकर आत्मनिर्भरता और सफलता की नई मिसाल प्रस्तुत की है। मातृछाया उत्पादक महिला समूह की सदस्याएं आज न केवल स्वयं प्राकृतिक खेती कर रही हैं, बल्कि अन्य किसानों को भी जैविक कृषि के लिए प्रेरित कर रही हैं।

समूह की महिलाओं ने बताया कि बिहान से जुड़ने से पहले वे धान, गेहूं, चना एवं सब्जियों की खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करती थीं। बढ़ती लागत और घटते लाभ के कारण खेती लाभकारी नहीं रह गई थी। इसके साथ ही खेतों की मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित हो रही थी। ऐसे समय में बिहान और कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसान गोष्ठियों, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं तकनीकी मार्गदर्शन ने उनकी खेती की दिशा बदल दी।

प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद समूह की महिलाओं ने घनजीवामृत, जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र एवं अग्नियास्त्र जैसे जैविक उत्पादों का निर्माण प्रारंभ किया। इनका उपयोग अपने खेतों में करने से उत्पादन लागत में कमी आई तथा मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। महिलाओं ने जैविक खेती के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए गांव के अन्य किसानों को भी प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए प्रेरित किया।

मातृछाया उत्पादक महिला समूह द्वारा तैयार जैविक उत्पादों एवं खेती के मॉडल को विकासखंड और जिला स्तरीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जाता है, जहां उन्हें सराहना और पहचान मिल रही है। समूह की सदस्याएं नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर नई कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर रही हैं। समूह की महिलाओं ने बताया कि बिहान और कृषि विभाग के सहयोग से उन्हें एक नई पहचान मिली है। आज वे आत्मविश्वास के साथ सफल महिला किसान के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं और ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, बिहान मिशन एवं कृषि विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

बेरला अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना बेरला अंतर्गत रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्र डंगनिया (ब) 02 (डोलीपारा), ग्राम पंचायत डंगनिया (ब) में आंगनबाड़ी सहायिका का पद रिक्त है जिस पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भर्ती की जाएगी।

इस पद के लिए इच्छुक एवं पात्र महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया नवीन ई-भर्ती पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। अभ्यर्थी 22 जून 2026 से 06 जुलाई 2026 तक निर्धारित पोर्टल https://aww.e-bharti.in/ पर जाकर आवश्यक दस्तावेजों सहित पंजीयन कर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ई-भर्ती पोर्टल के यूजर मैनुअल में उपलब्ध है। आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है। इस पद के लिए वही महिलाएं आवेदन करने की पात्र होंगी जो संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड की स्थानीय निवासी हों, जिस वार्ड/ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए विज्ञापन जारी किया गया है।

सभी ग्राम पंचायतों और आश्रित ग्रामों में आज से होगा ग्राम सभा का आयोजन

पीएमवाय के अंतर्गत आवास प्लस 2 .0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची पर ग्राम सभा मे क्या होगा

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

कबीरधाम जिले के 471 ग्राम पंचायतों और उनके आश्रित ग्रामों में 24 जून 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम सभा में 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका ग्रामीण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 की स्थाई प्रतीक्षा सूची पर चर्चा होगी जिसमे शासन की दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय पर ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी।

कलेक्टर गोपाल वर्मा द्वारा ग्राम सभा का आयोजन करने के निर्देश जारी किए गए है। ग्राम सभा मे महात्मा गांधी नरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी योजना से ग्रामीणों को मिलने वाले 125 दिनों के रोजगार, सात दिवस में मजदूरी भुगतान, काम की मांग पर रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, आजीविका, जल संरक्षण के साथ महिलाएं एवं युवाओं को मिलने वाले फायदे के बारे में बताया जाएगा। साथ ही वर्तमान मजदूरी दर बेरोजगारी भत्ता पारदर्शिता एवं जवाबदेही जैसे प्रमुख बदलाव के विषय में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी।

नई योजना में कार्य की चार प्रमुख श्रेणियां जिसमें जल सुरक्षा और संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रमुख घटकों पर ग्रामीणों के साथ चर्चा होगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपसंचालक पंचायत राज तिवारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जिले में ग्राम सभा का आयोजन होगा जिसमें शासन की प्रमुख योजनाओं पर बात होगी।

ग्राम सभा मे मुख्य रूप से विकसित भारत जी राम जी एवं प्रधानमंत्री आवास प्लस 2.0 की स्थाई प्रतीक्षा सूची का विषय है। इसके अतिरिक्त जल संवर्धन, ग्राम संपदा एप्प, स्वच्छता, टीवी मुक्त भारत अभियान एवं बाल विवाह जैसे विषयों पर सूचीबद्ध हितग्राहियों के नाम का वाचन ग्राम सभा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिले में कुल 1,30,056 सर्वेक्षित हितग्राहियों का नाम सूची में शामिल है। जिसमें जनपद पंचायत बोड़ला में 27970, कवर्धा में 30616, पंडरिया में 45073 एवं स.लोहारा में 26397 ग्रामीण हितग्राही परिवार शामिल है। इसके साथ ही विशेष ग्राम सभा में पूरी सूची का वाचन किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी पात्रता का परीक्षण करा सकता है। प्राप्त आपत्तियों पर जांच परीक्षण उपरांत निराकरण करते हुए हितग्राहियों की अंतिम सूची तैयार की जावेगी। पारदर्शिता के साथ योग्य लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अंतिम सूची को अनुमोदन के पश्चात आवास प्लस 2.0 के पोर्टल में अपलोड किया जाएगा जिससे पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभांवित किया जा सके।

अनुपस्थित कर्मचारी को तत्काल कार्य पर उपस्थित होने के निर्देश, अन्यथा होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता द्वारा उपखंड कवर्धा में पदस्थ चैकीदार जीवाराखन ध्रुव को तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होने अथवा अपनी वर्तमान स्थिति एवं अनुपस्थिति के संबंध में विभाग को सूचना देने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीवाराखन ध्रुव, चैकीदार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड कवर्धा, 10 अक्टूबर 2025 से बिना अनुमति एवं बिना किसी सूचना के अपने कार्य से निरंतर अनुपस्थित हैं। विभाग द्वारा उनकी अनुपस्थिति के संबंध में कई बार पत्राचार किया गया है। उनके गृह ग्राम मोहतरा, पोस्ट नटवा, तहसील एवं जिला बलौदाबाजार के पते पर भी सूचना प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड कवर्धा के माध्यम से भी उन्हें लगातार कार्य पर उपस्थित होने के लिए पत्र भेजे गए हैं। इसके बावजूद संबंधित कर्मचारी द्वारा न तो विभाग को कोई सूचना उपलब्ध कराई गई है और न ही वे अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हुए हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कार्यपालन अभियंता ने निर्देशित किया है कि जीवाराखन ध्रुव जहां कहीं भी हों, वे तत्काल अपने कार्य पर उपस्थित हों अथवा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में विभाग को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित कर्मचारी द्वारा शीघ्र कार्य पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की होगी।

36 युवा फेलोज बनेंगे सुशासन के नए वाहक, नीति निर्माण से प्रशासनिक सुधारों तक निभाएंगे अहम भूमिका

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर के संयुक्त प्रयास से संचालित मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के अंतर्गत एमबीए (पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस) 2026-28 बैच के ओरिएंटेशन एवं उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन आईआईएम रायपुर में किया गया। इस पहल के माध्यम से राज्य के युवाओं को प्रशासनिक दक्षता, नीति-निर्माण और जनसेवा के क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के अंतर्गत राज्य के 19 जिलों से चयनित 36 प्रतिभाशाली युवाओं को एमबीए (पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस) की दो वर्षीय डिग्री प्रदान की जाएगी। चयनित फेलोज में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 12 तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 4 अभ्यर्थी शामिल हैं। यह कार्यक्रम राज्य के युवाओं को शासन व्यवस्था की जमीनी समझ प्रदान करते हुए उन्हें परिवर्तनकारी नेतृत्व के रूप में विकसित करेगा।

फेलोशिप के दौरान प्रतिभागी 5 माह तक आईआईएम रायपुर में उच्च स्तरीय अकादमिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जबकि 19 माह तक राज्य शासन के विभिन्न विभागों और जिलों में कार्य करते हुए नीति-निर्माण, कार्यक्रम क्रियान्वयन, प्रशासनिक नवाचार तथा सुशासन के व्यावहारिक पहलुओं का अनुभव हासिल करेंगे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्यमंत्री सचिवालय तथा सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत ने अपने संबोधन में कहा कि सुशासन केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन, नागरिकों तक सेवाओं की समयबद्ध पहुंच और परिणामोन्मुखी प्रशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से जनसेवा, नैतिक नेतृत्व, नवाचार और उत्तरदायित्व के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विशेष सचिव रजत बंसल एवं संयुक्त सचिव मयंक अग्रवाल ने विद्यार्थियों के साथ डिजिटल गवर्नेंस, प्रशासनिक सुधार, नीति-निर्माण और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया से जुड़े अनुभव साझा किए तथा उन्हें राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

सेक्टर-06 स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में भव्य 'अरुण स्तंभ' की हुई स्थापना

समाजसेवी स्व . दिलीप सतपथी की स्मृति को किया गया चिरस्थायी

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

उत्कल समाज के प्रतिष्ठित समाजसेवी, शिक्षाविद और महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी के परम भक्त दिवंगत स्व. दिलीप सतपथीकी पावन स्मृति में आज सेक्टर-06 स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में भव्य 'अरुण स्तंभ' की स्थापना की गई। जगन्नाथ संस्कृति और समाज सेवा के प्रति उनके अद्वितीय समर्पण को जीवंत रखने के लिए उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अदिति सतपथी द्वारा इस स्तंभ की स्थापना का संकल्प लिया गया था, जो आज विधि-विधान के साथ पूर्ण हुआ।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान:-22 जून को आयोजित इस पावन कार्यक्रम में मुख्य पुरोहित पंडित तुषार महापात्र द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार और संपूर्ण विधि-विधान के साथ अरुण स्तंभ की स्थापना व पूजा-अर्चना संपन्न कराई गई। इस मांगलिक अनुष्ठान में सीमांचल बेहेरा एवं श्रीमती ज्योत्सना बेहेरा ने मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित रहकर सभी धार्मिक कार्यों को श्रद्धापूर्वक पूर्ण किया। इस अरुण स्तंभ को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के खिचिंग से मंगाया गया है। इस अवसर पर जगन्नाथ समाज के गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

क्या है अरुण स्तंभ और इसका महत्व:- अरुण स्तंभ का महत्व: मूल रूप से ओड़िशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार के सामने स्थापित 'अरुण स्तंभ' का जगन्नाथ संस्कृति में अत्यंत उच्च धार्मिक महत्व है। यह 16 कोणों वाला एक भव्य एकश्म स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर सूर्य के सारथी 'अरुण' विराजमान हैं। मान्यता है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस स्तंभ के दर्शन और स्पर्श से श्रद्धालु के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सेक्टर-06 जगन्नाथ मंदिर में इसकी प्रतिकृति की स्थापना से स्थानीय श्रद्धालुओं को अब यहीं पुरी धाम की दिव्यता का अनुभव हो सकेगा।

स्व. दिलीप सतपथी उत्कल समाज के एक ऐसे प्रकाश स्तंभ थे, जिन्होंने न केवल जगन्नाथ संस्कृति के उन्नयन और प्रचार-प्रसार में अपना जीवन समर्पित किया, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अद्वितीय मिसाल कायम की। उन्होंने समाज के गरीब और मेधावी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने जैसे कई अनुकरणीय प्रयास किए। उनकी इसी जन-कल्याणकारी सोच और महाप्रभु के प्रति उनकी अगाध आस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए उनकी धर्मपत्नी द्वारा यह सराहनीय पहल की गई है। अदिति सतपथी ने इस अवसर पर भावुक होते हुए कहा कि "महाप्रभु श्री जगन्नाथ के प्रति उनका (स्व. दिलीप जी का) समर्पण अटूट था। यह अरुण स्तंभ न केवल उनकी पावन स्मृति को संजोए रखेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी जगन्नाथ संस्कृति और जनसेवा से जुड़ने की प्रेरणा देगा।"

कांकेर में नक्सल डंप का भंडाफोड़, पुलिस व बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में हथियारों का किया जखीरा बरामद

नई दृष्टिबिंदु / कांकेर

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिसव बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों द्वारा डंप किए गए हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की गई। यह कारवाई मंगलवार को थाना छोटेबेठिया, जिला कांकेर के ग्राम आमाटोला के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में हुई। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए सघन सर्चिंग अभियान के दौरान यह नक्सल डंप मिला।

डंप से कई महत्वपूर्ण नक्सल सामग्री और हथियार बरामद किए गए। कारवाई के दौरान चार भरमार बंदूकें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दो वायरलेस सेट भी मिले हैं। एक रेडियो भी बरामद किया गया है। एक नक्सल वर्दी और दो पोच भी जब्त किए गए। एक चार्जर और एक बैटरी भी मिली है। नक्सल साहित्य के साथ अन्य कई सामग्री भी बरामद हुई। कांकेर पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार संयुक्त अभियान संचालित किया जा रहा है। यह कार्रवाई जिला पुलिस, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम ने की है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सतकर्ता बरती जा रही है। सुरक्षा बल लगातार सघन सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है।

कांकेर पुलिस नक्सल प्रभावित इलाकों में सक्रिय है। यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। इस बरामदगी से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। उनके हथियारों और संचार साधनों की आपूर्ति बाधित हुई है। सुरक्षा बल लगातार नक्सल विरोधी अभियानों को तेज कर रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां समन्वय से काम कर रही हैं।

बारिश से पहले बेमेतरा के वार्डों में नालियों की साफ- सफाई शुरू

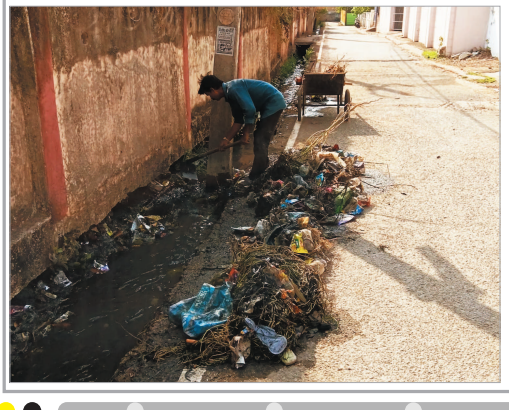

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

बेमेतरा वार्ड नंबर 8 में लगातार स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है, बरसात के पूर्व नालियों में कचरा ना जमें इसके लिए छोटी नाली हो या बड़ी नाली हो, मलमा को निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है, हर 5 से 7 दिन के अंदर नगर पालिका और प्रशासन के सहयोग से साफ सफाई कराई जा रही है, बेमेतरा जैसे बड़े क्षेत्र में वार्ड नंबर 8 के लिए केवल एक ही कर्मचारी मिला जिससे साफ सफाई कराई जा रही है, श्रीमती चांदनी रोशन दत पार्षद की सक्रियता से वार्ड नंबर 8 में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, परंतु वार्ड की सफाई के लिए केवल एक ही कमचारी पर्याप्त नहीं है, कभी-कभी वार्ड में सफाई के लिए ट्रैक्टर और जेसीबी की भी जरूरत होती है, जिन की पूर्ति के लिए नगर पालिका को और सजगता की जरूरत है।

प्रतिबंधित नशीली सामग्री और अवैध वस्तुओं की आपूर्ति रोकने पुलिस व खाद्य और औषधि विभाग की हुई बैठक

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग। कूरियर एवं ई-कॉमर्स सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित नशीली सामग्री, अवैध औषधियों तथा घातक हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से सोमवार को दुर्ग पुलिस एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक कंट्रोल रूम सेक्टर-06 दुर्ग में आयोजित हुई, जिसमें कूरियर सेवा संचालकों एवं विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी पार्सल की बुकिंग के दौरान प्रेषक, प्राप्तकर्ता तथा बुकिंग कराने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। इसके साथ ही सभी पार्सल बुकिंग केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा न्यूनतम एक माह तक फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए ताकि संदिग्ध गतिविधियों की स्थिति में जांच में सहायता मिल सके।

अधिकारियों ने कूरियर संचालकों को निर्देशित किया कि यदि किसी पार्सल में प्रतिबंधित नशीली औषधि, मादक पदार्थ या अन्य संदिग्ध सामग्री होने की आशंका हो तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को दी जाए। बैठक में औषधियों से संबंधित पार्सलों के लिए अलग रजिस्टर संधारित करने तथा भेजने वाले एवं प्राप्तकर्ता की संपूर्ण जानकारी दर्ज करने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही पार्सल बुकिंग के दौरान ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई ताकि जरूरत पड़ने पर लेन-देन और पहचान का सत्यापन किया जा सके।

बैठक के दौरान कूरियर सेवाओं के माध्यम से होने वाली संभावित अवैध गतिविधियों की रोकथाम, निगरानी व्यवस्था और संबंधित संस्थाओं की वैधानिक जिम्मेदारियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्य प्रकाश तिवारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक संचालक संजय सिंह, औषधि निरीक्षक विष्णु प्रसाद साहू, गायत्री पटेल, जागेश्वरी साहू सहित विभिन्न कूरियर कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों, कूरियर संचालकों और ई-कॉमर्स कंपनियों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध पार्सल, प्रतिबंधित नशीली सामग्री या अवैध वस्तुओं के परिवहन की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, जिससे कानून व्यवस्था और जनसुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

रायपुर निगम ने सेंट पॉल स्कूल परिसर में बने विवादित भवन को ढहाया

रायपुर। राजधानी रायपुर के सेंट पॉल स्कूल परिसर में बने एक विवादित सामुदायिक भवन पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। हिंदू स्वाभिमान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष विश्वदिनी पांडेय ने सामुदायिक भवन के नाम पर चर्च बनाए जाने का आरोप लगाया था और इसकी शिकायत भी की थी, जिसके बाद नगर निगम और जिला प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान स्थिति न बिगड़े, इसके लिए प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए सेंट पॉल स्कूल के दोनों तरफ की सड़कों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। मौके पर अपर कलेक्टर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सेंट पॉल स्कूल के पास बने विवादित भवन को बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया जा रहा है। इस पूरे मामले में हिंदू स्वाभिमान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष पांडेय का कहना है सेंट पॉल स्कूल परिसर एक शैक्षणिक संस्थान है। सेंट पॉल ट्रस्ट के पास इस जमीन की लीज साल 2022 में ही खत्म हो चुकी है। लीज समाप्त होने के बावजूद स्कूल परिसर में बिना किसी वैध अनुमति के सामुदायिक भवन के नाम पर चर्च का निर्माण किया जा रहा था।

GOSWWAMI
FLEX PRINTING
ADVERTIZER
भिलाई में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा
Hoardings • Flex Banner • Vinyl Printing
One Way Vision • Glow Sign Board
93290-13334, 74711-15735
goswamiflex@gmail.com
Address - 3rd Floor Shop No-1, Arora Tower, M.G. Market

राज्य सरकार का बड़ा फैसला : सहकारी बैंक अनियमितता पर कड़ा प्रहार

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कृषि मंत्री नेताम के विशेष प्रयास रंग लाए, ईडी जांच का किया स्वागत, सैकड़ों किसानों को मिली राहत ; खाद-बीज वितरण फिर शुरू

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की शंकरगढ़, कुसमी, रामानुजगंज तथा रामचंद्रपुर क्षेत्र की समितियों में वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रभावित किसानों को राहत प्रदान की है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम के विशेष प्रयासों और किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप अब प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को पुनः खाद एवं बीज मिलना शुरू हो गया है।

गौरतलब है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की शंकरगढ़, कुसमी, रामानुजगंज तथा रामचंद्रपुर क्षेत्र की समितियों में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं और गबन के मामलों ने सैकड़ों किसानों को प्रभावित किया था। अनियमितताओं के कारण किसानों को समय पर नकद ऋण, खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, जिससे उनमें असंतोष का वातावरण बन गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बैंक प्रशासन और राज्य सरकार ने दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की। कई कर्मचारियों को निलंबित किया गया तथा संबंधित मामलों की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार प्रभावित शाखाओं से जुड़े लगभग 497 किसानों की शिकायतों में 30 करोड़ 51 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता सामने आई है।

सरकार ने किसानों को राहत देने के उद्देश्य से त्वरित कार्ययोजना बनाते हुए संबंधित समितियों को पात्र किसानों की सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। सूची प्राप्त होने के बाद ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया तेजी से शुरू की जा रही है, ताकि किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक खाद, बीज और अन्य सुविधाएं समय पर मिल सकें। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों को सहूलियत प्रदान करना और उनकी कृषि गतिविधियों को निर्बाध बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मंत्री नेताम ने यह भी कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है और उन्होंने ईडी की जांच का स्वागत किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि निष्पक्ष जांच से पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी तथा दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों में भरोसा बढ़ा है। खाद-बीज वितरण व्यवस्था के पुनः शुरू होने से किसानों को बड़ी राहत मिली है और आगामी कृषि सीजन की तैयारियों को नई गति मिली है। सरकार का कहना है कि किसानों के हितों की रक्षा और सहकारी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अर्चना
फ्लाई ऐश ब्रिक्स
निर्माता एवं विक्रेता
हैवी इंडस्ट्रीयल एरिया, भिलाई
8 इंच एवं 9 इंच में उपलब्ध है।
संपर्क करें
9329960605, 9827160605, 9098639991

Baked by Suhani
Premium Homemade Cakes & Desserts
Birthday Cakes
Anniversary Cakes
Custom Theme Cakes
Serving Bhilai & Durg
baked.by.suhani
Suhani Singh
Premium Homemade Cakes & Desserts
Serving Bhilai & Durg
DM for Order
Followed by _s_andeep
Follow
Message
Order Now:
@baked.by.suhani
M0.6263734520

10वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पास छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए
फायर एवं सेफ्टी प्रशिक्षण
नौकरी में सहायक
प्रवेश प्रारंभ सत्र 2026-2027
निजी कंपनियां जैसे पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत नौकरियाँ मिलती है।
प्रशिक्षण शुल्क में विशेष छूट
सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा
फायर एवं सेफ्टी प्रशिक्षण में प्रवेश प्रारंभ

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	क्र.	पाठ्यक्रम का नाम
1.	फायर टेक्नोलॉजी एण्ड इंडस्ट्रियल सेफ्टी	5.	पी. जी. कोर्स व्यावसायिक सेफ्टी, स्वास्थ्य व पर्यावरण मैनेजमेंट सिस्टम
2.	इंडस्ट्रियल सेफ्टी / पी. जी. इंडस्ट्रियल सेफ्टी	6.	हैल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर
3.	बी.एस.सी. इन फायर सेफ्टी	7.	सब- फायर ऑफिसर
4.	पी. जी. कोर्स फायर एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी	8.	सर्टिफिकेट इन फायरमैन-इंडस्ट्रियल सेफ्टी

(An Authorized Training Centre of AEERO)
फायर सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट
(मान्यता प्राप्त निजी प्रशिक्षण संस्थान)
कैंपस :- इंदिरा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़
ADMISSION HELPLINE: 7697212782

BA
BCA
BCom
BBA
BSc
PGDCA
MSc CHEMISTRY
MSc BIOTECHNOLOGY
MSc BOTANY
MSc ZOOLOGY
MSc COMPUTER Sc
MSc MATHS
MA ENGLISH
MCom
BLib
MLib
DCA
MA CHHATTISGARHI
Affiliated to Hemchand Yadav University, Durg
SAI COLLEGE
Street-69, Sector-6, Bhilai
70248 86996
99770 01027
Deepak Advertisers

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100